PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 198 ● भिलाई, गुरुवार 12 फरवरी 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

पहला कॉलम

भाजपा नेता व पूर्व मंत्री मदन चौहान पर जानलेवा हमला

हापुड़ । जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मदन चौहान पर फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। घटना कोतवाली क्षेत्र के गांव हिरणपुरा के पास की बताई जा रही है। गनीमत यह रही कि बदमाशों द्वारा पिस्टल का ट्रिगर दबाने के बावजूद गोली नहीं चली और एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस के अनुसार, पूर्व मंत्री मदन चौहान गांव हिरणपुरा में एक सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही वह गांव के समीप पहुंचे, तभी सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार में सवार तीन से चार युवकों ने उनकी गाड़ी को अचानक रोक लिया। आरोप है कि बदमाशों ने मदन चौहान के साथ अभद्रता की और उन पर पिस्टल तान दी।

एनसीआर में बदलते मौसम और प्रदूषण का दोहरा असर

नोएडा। एनसीआर दिल्ली-नोएडा-गाजियाबाद में मौसम के लगातार बदलते मिजाज और वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर ने लोगों की सेहत पर गंभीर असर डालना शुरू कर दिया है। जिला अस्पतालों की ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों में करीब 50 प्रतिशत मरीज मौसमी बीमारियों से पीड़ित पाए जा रहे हैं। खासतौर पर उल्टी, दस्त, बुखार, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और एलर्जी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 10 से 12 फरवरी तक एनसीआर में मौसम में हल्की धुंध बनी रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। सुबह और शाम हल्की ठंड जबकि दिन में तेज धूप का असर लोगों को बीमार कर रहा है। वहीं, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई लाल श्रेणी में दर्ज किया गया।

मैकेनिक की आड़ में बिश्नोई गैंग के लिए हथियार सप्लाई करता था आरोपी आसाराम

मुंबई । फिल्म निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच नए-नए खुलासे कर रही है। अब पुलिस के हाथ नई जानकारी लगी है। पता चला है कि हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार आरोपी आसाराम फासले पिछले चार सालों से बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा था। आसाराम गैरेज मैकेनिक की आड़ में यह सब कर रहा था। फासले पुणे के मालवली इलाके का रहने वाला है और पिछले दस साल से वारजे क्षेत्र के एक गैरेज में मैकेनिक के तौर पर काम करता आ रहा था। जांच में सामने आया कि वह शुभम लोनकर से बहुत प्रभावित था। लोनकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी सदस्य है। फासले ने चार साल पहले लोनकर के प्रभाव और इलाके में उसके दबदबे को देखकर बिश्नोई गैंग जॉइन कर लिया था।

लोकसभा में राहुल गांधी का बड़ा आरोप

पीएम मोदी ने भारत माता को बेच दिया,किरेन रिजिजू ने मांगा सबूत..

नई दिल्ली/ एजेंसी

आज बजट सत्र का दसवां दिन है और लोकसभा की कार्यवाही में नेता विपक्ष राहुल गांधी का भाषण शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि बजट में वर्तमान चुनौतियों का कोई उल्लेख नहीं है, और विशेषकर एआई और डेटा से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि आज के दौर में एआई अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेता विपक्ष ने कहा कि हम युद्ध के युग में जी रहे हैं। रूस-यूक्रेन में संघर्ष जारी है, चीन अमेरिका को चुनौती दे रहा है, और ऊर्जा व वित्तीय साधन अब हथियार बन चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के इन संघर्षों के बीच हमारे बजट में कोई रणनीति नहीं है। राहुल गांधी ने अमेरिका और भारतीय डेटा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत की बड़ी आबादी हमारी ताकत है, लेकिन यह तभी उपयोगी होगी जब इसे सही ढंग से समझा जाएगा। अगर इंडिया ब्लॉक के राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत कर रहे होते, तो इस डील में सबसे महत्वपूर्ण तत्व भारतीय डेटा होता। आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में भू-राजनीतिक संघर्ष तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका के प्रभुत्व को चीन, रूस और अन्य ताकतों से चुनौती मिल रही है। साथ ही, ऊर्जा और वित्तीय साधनों के शस्त्रीकरण का दौर जारी है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अमेरिका हमारे फैसलों को प्रभावित कर रहा है। कृषि क्षेत्र अमेरिका के लिए खोला गया, जिससे किसानों की अनदेखी हुई। उन्होंने अमेरिका के बढ़ते टैरिफ और प्रधानमंत्री की कथित चिंता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र का रक्षा बजट प्रभावित होता दिखता है और इसमें मिस्टर अडानी का नाम जुड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी एक सामान्य व्यवसायी नहीं हैं और उनकी कंपनी पर अमेरिका में केस चल रहा है। उनका कहना था कि यह कंपनी बीजेपी के वित्तीय ढांचे का हिस्सा है। इस पर रविशंकर प्रसाद और किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने अनिल अंबानी का भी उदाहरण दिया और पूछा कि वह जेल में क्यों नहीं हैं। इसका संबंध उन्होंने एपस्टीन फाइल से जोड़ा। इस पर भी सदन में आपत्ति उठी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हितों से समझौता किया है। उन्होंने भावनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि देश की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सदन में हंगामे जैसी स्थिति बन गई।

किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मांगा सबूत

राहुल गांधी के बयान के बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से सबूत मांगा है। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि सरकार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस (प्रिविलेज नोटिस) दाखिल करने जा रही है। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद तथा निराधार बयान देने का काम किया है। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया एवं आचरण के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि जब कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है, तो उसे पहले नोटिस देना अनिवार्य है ।

सिर्फ वादे नहीं....

रोजगार और स्टार्टअप्स के लिए ठोस रोडमैप तैयार- वित्तमंत्री सीतारमण

नई दिल्ली/ एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट बहस पर लोकसभा को संबोधित किया। लोकसभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की रणनीतिक प्राथमिकताओं के बारे में बताया और इससे जुड़े तथ्यों को सुव्यवस्थित तरीके से सदन के पटल पर रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने श्रम प्रधान क्षेत्रों को बजट में प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत बायोफार्मा सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्टार्टअप्स के विस्तार के लिए उन्हें बड़े डोमेन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताते हुए वित्त मंत्री ने साफ किया है कि मेगा टेक्सटाइल पार्कों के विकास के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम करने को पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस बजट में सकल कर प्राप्तियां 44.04 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह 2025-26 के अनुमानित राजस्व से लगभग 8 प्रतिशत अधिक है, यानी इसमें 3.26 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। यदि हम 2026-27 के कुल व्यय को देखें, तो यह 53.47 लाख करोड़ रुपये है, जो हमारी कर प्राप्तियों से कहीं अधिक है। पूंजीगत व्यय 12.22 लाख करोड़ रुपये आंका गया है, जो जीडीपी का 3.1 प्रतिशत है और 2025-26 के अनुमानित राजस्व से 11.5 प्रतिशत अधिक है... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर परिचर्चा के दौरान लोकसभा में बोलते हुए कहा, 16वें वित्त आयोग ने 2018-19 से 2022-23 तक केंद्र की ओर से राज्यों को हस्तांतरित किए गए राज्य के हिस्से का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि इन सभी वर्षों में केंद्र की ओर से किया गया हस्तांतरण वित्त आयोग की सिफारिश से बिल्कुल मेल खाता है।

दिल्ली में बनेंगे तीन नए मेट्रो कॉरिडोर

सीएम गुप्ता ने परियोजना को दी मंजूरी,यहां 13 नए स्टेशन बनेंगे....

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मेट्रो फेज-IV(ए) को स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने जानकारी दी कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कुल 16 किलोमीटर की लंबाई वाले तीन नए कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिनमें 13 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 12,014.91 करोड़ रुपये है, जिसमें दिल्ली सरकार का बजटीय हिस्सा 2,940.46 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इस परियोजना को वर्ष 2028 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वीकृत किए गए तीन कॉरिडोर में आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ (सेंट्रल विस्टा के रास्ते), तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज और एरोसिटी से इंदिरा गांधी डोमेस्टिक टर्मिनल-1 (आईजीडी टी-1) शामिल हैं। बनाए जाने वाले कुल 13 स्टेशनों में 10 स्टेशन अंडरग्राउंड और तीन स्टेशन एलिवेटेड होंगे। यह विस्तार मौजूदा मेट्रो नेटवर्क के साथ निर्बाध इंटरचेंज की सुविधा प्रदान करेगा और हवाई अड्डे, वाणिज्यिक केंद्रों व आवासीय क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। फेज-5(ए) का सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर आरके. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक प्रस्तावित है।

एयरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल-1 कॉरिडोर

फेज-5(ए) का दूसरा महत्वपूर्ण कॉरिडोर एयरोसिटी से इंदिरा गांधी घरेलू हवाई अड्डा टर्मिनल-1 (आईजीडी टी-1) तक प्रस्तावित है। इस कॉरिडोर की लंबाई 2.26 किलोमीटर है और इस पर एक स्टेशन प्रस्तावित है। यह कॉरिडोर हवाई यात्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा और एयरपोर्ट तक मेट्रो की सीधी, तेज और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगा। इससे निजी वाहनों और टैक्सियों पर निर्भरता कम होगी और एयरपोर्ट क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव घटेगा। इस परियोजना की लागत 1,419.64 करोड़ रुपये होगी। जिसमें 351.86 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार देगी।

बैंड बाजे वाले बयान पर बुरे फंसे प्रताप बाजवा, पंजाब राज्य अनुसूचित जाति कमीशन ने किया तलब

चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति कमीशन द्वारा बैंड बाजे वाली टिप्पणी करने के मामले में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को तलब कर लिया गया है। आयोग ने नोटिस भेजकर 11 फरवरी बाद दोपहर 3 बजे बाजवा को पेश होने के लिए कहा है। इस दौरान आयोग ने एसएसएपी अमृतसर से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। याद रहे कि लीडर ऑफ अपोज़िशन प्रताप सिंह बाजवा ने एक पॉलिटिकल रैली में कैबिनेट मिनिस्टर हरभजन सिंह श्वञ्जह्व का ज़िक्र करते हुए एक कमेंट किया था।

पोटाकेबिन घोटाले में बड़ा खुलासा

कागजों पर पेट भर रहे थे बच्चे,हकीकत में गायब था निवाला;चार अधीक्षक सस्पेंड.....

बीजापुर। जिले में शिक्षा की लौ जलाने के नाम पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह पैसा आदिवासी बच्चों के पेट तक पहुंचने के बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। इस मामले को प्रमुखता से उठाने के बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है। बीजापुर के पोटाकेबिनों आवासीय विद्यालयों में हुए वित्तीय अनियमितता और राशन घोटाले के मामले में संयुक्त संचालक शिक्षा ने चार प्रभारी अधीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच दल जब बीजापुर के विभिन्न पोटाकेबिनों में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। जिन विद्यालयों में कागजों पर बच्चों की उपस्थिति शत-प्रतिशत दिखाई गई थी। वहां मौके पर आधे बच्चे भी मौजूद नहीं थे। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच बड़ी संख्या में बच्चे अनुपस्थित थे। लेकिन उनके नाम पर राशन सब्जी और मेष शुल्क का पैसा सरकारी खजाने से लगातार

निकाला जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि अधीक्षकों ने अपनी चोरी छिपाने के लिए उपस्थिति पंजी में जमकर कांट-छांट और हेरफेर की। बच्चों की फर्जी उपस्थिति दर्ज कर शासन को लाखों रुपये का चूना लगाया गया। यह खेल केवल राशन तक सीमित नहीं था बल्कि बच्चों को मिलने वाली शिष्यवृत्ति की राशि में भी डाका डाला गया। बीजापुर पोटाकेबिन घोटाले की तह तक जाने पर एक भयावह सच सामने आया है। कलेक्टर की अनुशंसा पर गठित जांच समिति ने पाया कि इन आवासीय विद्यालयों में भ्रष्टाचार का एक सुनियोजित पेपर मॉडल चल रहा था।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात करते हुए।

1200 मौलवी और हजारों जुटेंगे

मुर्शिदाबाद में 'बाबरी' जैसी मस्जिद आज से बननी शुरू

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 'बाबरी जैसी मस्जिद' के निर्माण की घोषणा ने देश की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख और पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बुधवार से इस विवादित प्रोजेक्ट के औपचारिक निर्माण की शुरुआत करने की बात कही है जिसे लेकर बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक जुबानी जंग तेज हो गई है। हुमायूं कबीर के दावे के अनुसार, मस्जिद निर्माण का कार्य बुधवार दोपहर 12 बजे औपचारिक

रूप से शुरू किया गया।, निर्माण कार्य शुरू होने से पहले सुबह 10 बजे से करीब 1000 से 1200 मौलाना, मुफ्ती और धर्मगुरुओं ने पवित्र कुरान की तिलावत (धार्मिक पाठ) करेंगे।

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन

अब जन गण मन से पहले बजेगा वंदे मातरम् जानिए क्या हैं नियम

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का मकसद यह स्पष्ट करना है कि वंदे मातरम को भी उसी गरिमा और आदर के साथ प्रस्तुत किया जाए, जैसा देश के अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों को दिया जाता है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, अब जब भी वंदे मातरम किसी सरकारी कार्यक्रम, सरकारी स्कूल के आयोजन या अन्य आधिकारिक समारोह में बजाया जाएगा, वहां मौजूद सभी लोगों को उसके सम्मान में खड़ा रहना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने यह भी तय किया है कि वंदे मातरम का पूरा छह छंदों वाला संस्करण, जिसकी अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकेंड है, अब राष्ट्रगान जन गण मन से पहले बजाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों की अपनी अलग पहचान और महत्व है। यदि किसी आयोजन में दोनों को एक साथ गाया या बजाया जाता है, तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जन गण मन प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे समय के दौरान लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा। नई गाइडलाइन के तहत कई महत्वपूर्ण सरकारी अवसरों पर वंदे मातरम बजाने की व्यवस्था की गई है। इसमें तिरंगा फहराने के मौके,

राष्ट्रपति के आगमन और राष्ट्र के नाम उनके संबोधन से पहले और बाद की स्थिति शामिल है। इसके अलावा राज्यपालों के आगमन, उनके भाषणों और नागरिक सम्मान समारोहों, जैसे पद्म पुरस्कार वितरण कार्यक्रमों में भी वंदे मातरम बजाया जाएगा, खासकर जब राष्ट्रपति कार्यक्रम में मौजूद हों। हालांकि, सरकार ने यह साफ किया है कि ये नियम सिनेमाघरों पर लागू नहीं होंगे। यानी फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना या दर्शकों का खड़ा होना अनिवार्य नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन निर्देशों का उद्देश्य किसी पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि वंदे मातरम के सम्मान को लेकर एक स्पष्ट और समान व्यवस्था तय करना है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष वंदे मातरम को लेकर विवाद सामने आया था, जब कुछ संगठनों ने इसके पाठ पर आपत्ति जताई थी और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे पर हंगामा हुआ था। ऐसे में नए दिशा-निर्देशों को सरकार की ओर से वंदे मातरम की परंपरा और राष्ट्रीय भावना को मजबूती देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

संरक्षण, संवर्धन के अभाव और उपेक्षा के चलते नगर के कुओं का अस्तित्व संकट में

बालोद। देखरेख, सफाई और उचित संवर्धन के अभाव में पारंपरिक कुओं का अस्तित्व तेजी से मिट रहा है। नगर के धरोहर कुओं में आज साफ मीठा पानी के बजाय कचरों का अंबार और गंदगियां ही मिलेगी। आधुनिक जल प्रणालियों (नल) की उपलब्धता, जन जागरूकता में कमी और शहरीकरण के कारण ये जलस्रोत गंदगी के ढेर या कचरे के डिब्बे बन गए हैं। ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व के बावजूद, ये कुएं अब उपेक्षा के कारण सूख चुके हैं। नगरपालिका बालोद अंतर्गत कुओं की हालत बहुत गंभीर है। एक ऐसा समय था जब इन्ही कुएं से बालोद नगर वासियों का प्यास बुझती थी। आज लोग इस कुएं को देख भी नहीं रहे है, जो पूरा बंजर हो गया है। जब घरों में नल नहीं हुआ करते थे, तब कुएं का उपयोग होता था, आज घरों में नल हो जाने के कारण कुएं को लोग भूलते जा रहे है। नगरपालीका अंतर्गत क्षेत्र में 15 से अधिक सार्वजनिक कुएं हैं। जो देखरेख के अभाव में बंजर बन गए है। प्राप्त जानकारी अनुसार नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत क्रमांक-01 प्राथमिक शाला पाररास, वार्ड क्रमांक-04 बुधवारी बाजार, वार्ड क्रमांक 04 पुस्तकालय के पास, वार्ड क्रमांक-07 हवलदार कुआं, वार्ड क्रमांक-10 पुलिस लाइन में कुंआ, वार्ड क्रमांक-10 पुराना थाना के पास, वार्ड क्रमांक-10 मस्जिद के पास, वार्ड क्रमांक-16 दूध गंगा के पास, वार्ड क्रमांक-15 कुन्दरूपारा, वार्ड क्रमांक-12 आमापारा, वार्ड क्रमांक-14 सिचाई कालोनी, वार्ड क्रमांक-15 पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, वार्ड क्रमांक-20 बूढ़ापारा, वार्ड क्रमांक-19 मैलाखांचा और उड़िया बस्तीवार्ड क्रमांक-19 में सार्वजनिक कुएं स्तिथ हैं। जिनमें कुछ का अस्तित्व खत्म हो चुका और और कुछ खत्म होने के कगार पर हैं।

कई वर्षों से कुओं की नही जो रही सफाई

नगर के वार्ड-10 पुराना थाना के पास कई वर्ष पुराना कुआं है। पहले लोग इसके पानी को पीने, खाना बनाने, नहाने व अन्य चीजों में उपयोग करते थे। घरों में नल उपलब्ध हो जाने से कुएं का उपयोग कम हो गया, धीरे धीरे कुआं बंजर होते गया और आज कुआं पूरा बंजर हो गया। वार्ड के पूरनलाल निर्मलकर, अशोक, राधेश्याम ने बताया कि पहले नगर पालिका वाले साफ सफाई करते थे। कई वर्ष से इसका सफाई नहीं हुआ है। लोग बंजर होजे से कुएं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका पानी मीठा था। आज इसका जल पूरा दूषित हो गया है। कुएं का उपयोग नहीं होने के कारण कुएं के ऊपर जाली लगा दिया गया ताकि बच्चे इस में गिर न जाए। अब बस यह कुआं नाम मात्र का रह गया है। वार्ड-10 में स्तिथ कुआं वन विभाग का है। आज यह कुआं गंदगियों से ढक गया है। यह अंग्रेज जमाने का कुआं है, पहले इसके पानी को पीने, नहाने एवं अन्य चीजों में उपयोग करते थे। आज भी पीने में उपयोग होता है, पर पहले के मुकाबले कम होता है। राजेश कौशिक, मनीष, जयसमुख और गणेश ने बताया कि इसके पानी का उपयोग आसपास के होटलो व अन्य दुकानों में होता है। यहां का पानी मीठा है और सफाई कम होती है।

वार्ड-4 स्तिथ कुआं कई सालों से सूखा

आमापारा चौक कलामंच वार्ड 12-13 पर स्तिथ कुएं का पानी मीठा है, इस कुएं का पानी लोग रोज पीने, खाना बनाने, नहाने में इस्तेमाल करते है। नलों में पानी 15-20 मिनट ही चलता है जिसके कारण आमापारा वासी के एक मात्र सहारा कुआं ही है। वार्ड वासी महेश, बृजलाल ने बताया कि कुआं लगभग सौ साल पुराना है। पुराने समय से अभी तक यह लोगो की प्यास बुझा रहा है। वार्ड-4 में स्तिथ कुआं करीबन 60-70 साल पुराना है। इसकी हालत आज बहुत खराब है। यह कई सालों से सुखा पड़ा है। कुएं के अंदर में पूरा गंदगी भरी है। बारिश का पानी थोड़े समय के लिए भरा रहता है, पर उसके बाद पूरा साल कुआं सुखा रहता है। अवधेश गुप्ता एवं गणेश चितसागर ने बताया कि आसपास में बोर का उपयोग होने से कुआं का पानी कुएं में नहीं ठहरता है। पहले लोग यहां से पानी भरा करते थे। जिसका उपयोग लोग खाना बनाने में, पीने में करते थे, पर आज कुएं के अंदर कचरे पौधे ही दिखाई दे रहे है। इसी वार्ड में एक और कुआं है। जो भी 50-60 साल पुराना है। कुएं के उपर पिल्हर खड़ा कर एक पुस्तकालय बनाया गया हैं। मिलन ठाकुर में बताया कि पहले समय में यह कुआं लोग की प्यास बुझाता था, व यहां का पानी अन्य चीजों में उपयोग होता था। होटलों में पानी के लिए उपयोग होता था। लेकिन कुआं आज ढक गया है। रास्ता नहीं हैं, और कुआं चारों दिशा से घिर चुका हैं।

कुओं के अस्तित्व खोने के मुख्य कारण

बता दे कि नल से पानी की सुविधा आने के बाद लोग कुओं के पानी का इस्तेमाल कम करने लगे है। उपेक्षा के चलते कुएं गंदगी और कूड़े का पर्याय बन गए हैं, जिससे वे अशुद्ध हो गए हैं। कुओं के आसपास कंक्रीट की संरचनाओं के निर्माण से भूजल पुनर्भरण (ग्राउंड वाटर रिचार्ज) कम हो गया है। साथ ही प्राचीन और ऐतिहासिक कुओं के जीर्णोद्धार पर स्थानीय प्रशासन व नगर पालिका का ध्यान नहीं जा रहा है। वही कभी कुएं सामुदायिक संपत्ति होते थे, लेकिन अब सामुदायिक भागीदारी के अभाव में इनका रखरखाव नहीं हो पा रहा हैं। जैसे-जैसे नई जल प्रणालियाँ आई है, कुओं के उपयोग में कमी आई, और उनके निर्माण तथा रखरखाव से जुड़ा सदियों पुराना पारंपरिक ज्ञान भी लुप्त होता चला गया। कभी कुएं बनाना और उनकी देखभाल करना एक सामुदायिक जिम्मेदारी थी, लेकिन अब यह सामूहिक भागीदारी धीरे-धीरे समाप्त हो गई है। हालांकि कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने गंगासागर तालाब और तांदुला की श्रमदान के जरिये सफाई करवाई थी।

अस्तित्व बचाने की आवश्यकता

जल संरक्षण की दिशा में जिला प्रशासन ने नीर चेतना अभियान और श्रमदान से हाल ही में तांदुला के जलकुंभी की सफाई की गई थी, ठीक वैसे ही अगर इन कुओं की ओर ध्यान दिया जाए, और जिम्मेदार अधिकारी एवं वार्ड के पार्षद अपनी जिम्मेदारी समझे तो जल संकट और गिरते भूजल स्तर (ग्राउंड वाटर लेवल) के बीच ये कुएं फिर से अत्यंत उपयोगी साबित हो सकते हैं। कुछ स्थानों पर इनके जीर्णोद्धार से जल संरक्षण के अच्छे परिणाम मिले हैं। इन ऐतिहासिक धरोहरों को साफ करने और इन्हें पुनर्जीवित करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि इन्हें गंदगी का घर बनने से बचाया जा सके।

वनांचल क्षेत्र मल्दामाल में हुआ विराट हिन्दू सम्मेलन का आयोजन

सरायपाली । विकास खंड के वनांचल क्षेत्र मल्दामाल में विराट हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिन्दू समाज को एकत्रित, संगठित, और जागरूक करना। यह कार्यक्रम कस्तूराबहाल के द्वारा हिन्दू सम्मेलन ग्राम पंचायत मल्दामाल के ग्रामीणों एवं पदाधिकारियों के सहयोग से किया गया। मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी आयोजन है, जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को जाति वर्ग ओर क्षेत्र के भेद भाव से ऊपर उठकर एकत्रित, संगठित और जागरूक करना है। इन सम्मेलनों के माध्यम से सनातनी पहचान, सामाजिक समरसता, और राष्ट्र निर्माण पर चर्चा की गई ताकी हिंदुओं की सोई हुई शक्ति को जगाया जा सके। कार्यक्रम के मुख्यअतिथि पंडित डोलामणि होता , मुख्य वक्ता आदित्य साहू, प्रांतीय सेविका भारतीय ठाकुर, जिला सेविका अनिता चौधरी, पुरूषोतम प्रधान सभी अतिथियों का मार्गदर्शन मिला।

जिसमें जिला पंचायत सभापति महासमुन्द एवं भाजपा जिला मंत्री

भोरमदेव शक्कर कारखाना बना गन्ना किसानों की आर्थिक मजबूती का आधार, 46.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर रचा भरोसे का नया अध्याय

कवर्धा। भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा गन्ना किसानों के लिए भरोसे और राहत का मजबूत केंद्र बनकर उभरा है। कारखाने द्वारा हाल ही में 6.93 करोड़ रुपये की राशि गन्ना किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई है। इसके साथ ही अब तक किसानों को कुल 46.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिससे हजारों किसान परिवारों को सीधा लाभ मिला है। यह उपलब्धि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के सतत प्रयासों का प्रतिफल मानी जा रही है, जिनके मार्गदर्शन में किसानों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया गया। वहीं कलेक्टर एवं कारखाने के प्राधिकृत अधिकारी श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और निरंतर बनाए रखा गया है। नियमित भुगतान से किसानों का सहकारी व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हुआ है।

पेराई व उत्पादन में निरंतर प्रगति- कारखाना प्रबंधन के अनुसार चालू पेराई सत्र में अब तक 2 लाख 33 हजार 455 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई पूरी की जा चुकी है, जिससे 2 लाख 74 हजार 322 क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ है। यह सफलता किसानों के सहयोग, प्रशासनिक मार्गदर्शन और कारखाने की बेहतर कायकुशलता का संयुक्त परिणाम है।

सहकारिता को सशक्त करने की दिशा में पहल- कारखाना प्रबंधन ने शेयरधारक सदस्य किसानों एवं गैर-सदस्य गन्ना उत्पादकों से अपील की है कि वे सर्वे के अनुरूप अधिकतम गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित करें। प्रबंधन का मानना है कि पर्याप्त गन्ना उपलब्ध होने से पेराई अवधि बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी और भविष्य में भी किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उपविधि प्रावधानों से अनुशासन और स्थायित्व- कारखाने की

पंजीकृत उपविधियों के अंतर्गत सदस्य किसानों के लिए गन्ना आपूर्ति अनिवार्य रखी गई है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि इन प्रावधानों का उद्देश्य दंडात्मक नहीं, बल्कि सहकारी संस्था की निरंतरता और किसानों के दीर्घकालिक हितों की सुरक्षा है।

किसानों के हित में बहुआयामी प्रयास- भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना केवल भुगतान तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों की समग्र उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत है। एफआरपी के अतिरिक्त रिकवरी राशि, शासन द्वारा घोषित बोनस, रियायती दर पर शक्कर वितरण, उन्नत बीज उपलब्धता, प्रशिक्षण व्यवस्था, कारखाना परिसर में बलराम सदन, मात्र 5 रुपये में गरम भोजन की कैंटीन जैसी सुविधाएं इसकी मिसाल हैं।

सामूहिक सहयोग से उज्ज्वल भविष्य की ओर- कारखाना प्रबंधन ने सभी गन्ना उत्पादकों से सामूहिक सहभागिता की अपील करते हुए कहा है कि किसानों के सहयोग से ही कारखाना और अधिक मजबूत बनेगा। इससे न केवल पेराई लक्ष्य पूरे होंगे, बल्कि क्षेत्र के गन्ना किसानों का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध होगा।

ताले में कैद पशु औषधालय, सड़क पर तड़पकर मरती बछिया, महराजपुर में सरकारी लापरवाही की क्रूर तस्वीर

कवर्धा। जहाँ सरकार पशु कल्याण और ग्रामीण विकास के दावे करती नहीं थकती, वहीं महराजपुर में पशु चिकित्सा व्यवस्था की सच्चाई बेहद शर्मनाक और अमानवीय रूप में सामने आई है। सड़क पर घायल बछिया घंटों तड़पती रही और अंततः दम तोड़ दिया, लेकिन पशु औषधालय (नया), महराजपुर का ताला नहीं खुला। घटना के दौरान ग्रामीणों ने जिम्मेदारी निभाते हुए पशु चिकित्सक को बार-बार फोन लगाया। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन डॉक्टर ने कॉल उठाना मुनासिब नहीं समझा। न इलाज मिला, न संवेदना – सिर्फ़ सिस्टम की बेरुखी। सबसे गंभीर सवाल यह है कि लाखों रुपये की लागत से बना पशु औषधालय भवन सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है। भवन मौजूद है, सुविधाएं कागजों में हैं, लेकिन डॉक्टर मुख्यालय से नदारद हैं। ताले में बंद औषधालय ग्रामीणों के लिए किसी धोखे से कम नहीं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति बनी, लेकिन हर बार सरकारी उदासीनता और गैर-जिम्मेदारी ही सामने आई। पशु, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उनके जीवन की कीमत इस व्यवस्था में शून्य होती जा रही है। महराजपुर की यह घटना न सिर्फ एक बछिया की मौत है, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता का पोस्टमार्टम है। सवाल साफ है – जब डॉक्टर मुख्यालय से गायब हैं तो जवाबदेह कौन। जब ताले नहीं खुलते तो भवन पर खर्च क्यों और जब जान चली जाए, तब जांच का क्या मतलब। महराजपुर में लाखों का औषधालय भवन ग्रामीणों की उम्मीदों पर विराम बन चुका है – एक ऐसा स्मारक, जो सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को बेनकाब करता है।

ग्रामों में 'रोजगार दिवस' और 'आवास दिवस' का आयोजन

दल्लीराजहरा। शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले के विभिन्न ग्रामों में 'रोजगार दिवस' और 'आवास दिवस' का आयोजन किया गया। इसमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सव का माहौल रहा, जहां शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच एवं पंचगण, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, आवास हितग्राहियों और मनरेगा श्रमिकों और भारी संख्या में ग्रामवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान न केवल योजनाओं की समीक्षा की गई, बल्कि आगामी लक्ष्यों के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित भी किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और वीबी-जी-राम-जी के प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान विभागीय कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण की तकनीकी बारीकियां, किस्तों का भुगतान और गुणवत्तापूर्ण आवास सुनिश्चित करना, वीबी-जी-राम-जी के तहत योजना के नवीन प्रावधानों और ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्थायी रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इस योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की रोजगार गारंटी। योजना के प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों को न्यूनतम आय सुरक्षा प्रदान करना जिससे बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक अस्थिरता को कम करना है। इसके साथ ही साथ मनरेगा श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर, समय पर भुगतान और श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। मनरेगा अंतर्गत संपादित कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण के तहत कार्यों का भौतिक सत्यापन योजना की पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की जानकारी दी गई। डिजिटल पारदर्शिता के तहत ग्रामीणों ने अपने मोबाइल के माध्यम से क्यू आर स्कैन के माध्यम से मनरेगा के कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने हितग्राहियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। प्रचार-प्रसार हेतु ग्राम पंचायतों में वीबी-जी-राम-जी का पांप्लेट वितरण एवं दीवार लेखन के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी गई ताकि अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

लोक कला महोत्सव एवं रंग महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा

बेमेतरा। बेमेतरा विधानसभा, अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरिया, सिलघट(भी) एवं लावातरा (ढा) मे जय मां शारदा सेवा व झांकी मंडली एवं विभिन्न समितियो द्वारा आयोजित लोक कला महोत्सव एवं रंग महोत्सव में पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा, उपस्थित हुए इस अवसर पर पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि जैसा की लोक कला महोत्सव एवं रंग महोत्सव हमारे धार्मिक संस्था का एक प्रमुख केंद्र है तथा गांव में एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है जिससे हमें सीख मिलती है कि अपने गांव में भाईचारा एकता, बनाए रखने के लिए लोक महोत्सव एवं रंग महोत्सव पर्व का त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है लोक कला तथा जस गायन के रूप में हम अपनी संस्कृति को समृद्ध करते हैं तथा रंग महोत्सव सतनाम समाज इससे न केवल आपसी भाईचारा बढ़ता है बल्कि गांव में रौनकता भी आती है। शक्ति की आराधना पूरे संसार में की जाती है और इसी शक्ति के आराधना हमारे ग्राम में हो रही है जो अत्यंत ही हर्ष का विषय है।

शिक्षा से संस्कार, शिक्षक से समाज का निर्माण होता है : दीपेश साहू

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक / समग्र शिक्षक फेडरेशन, जिला बेमेतरा द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मेलन एवं वार्षिक कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम नगर के प्रतिष्ठित होटल में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी जी.आर. चतुर्वेदी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात जिले के शिक्षक-शिक्षिकाओं द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे आयोजन को जीवंत बना दिया। मंचीय गायन-वादन, काव्य पाठ, नृत्य एवं रोचक सहभागितात्मक गतिविधियों ने दर्शक दीर्घा को पूरे दिन आनंदित किए रखा।

कार्यक्रम मे सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

इस कार्यक्रम मे गायन-वादन में जलेश्वर, डोमन साहू, धनेश रजक, लेखा रजक ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कवि सम्मेलन में सुनील शर्मा, ईश्वर साहू, जलेश्वर दास मानिकपुरी एवं दिलीप पटेल ने काव्य पाठ से खूब तालियाँ बटोरीं। नृत्य प्रस्तुति में भावना टंडन एवं छगन साहू ने आकर्षक प्रस्तुति दी। वहीं सुकन्या राजपूत, मनीषा कौशल सहित अन्य शिक्षिकाओं द्वारा कराई गई रोचक गतिविधियों ने पूरे सभागार को सहभागी बना दिया।

राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिकाओं का अभिनंदन

फेडरेशन द्वारा जिले की राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिकाओं– ज्योति बनाफर, हिमकल्याणी सिन्हा, सुनीता राजपूत सहित कार्यक्रम के प्रतिभागियों एवं अतिथियों का प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मान किया गया।

शिक्षक सदन की मांग

स्वागत भाषण में जिलाध्यक्ष पोखन साहू ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए बेमेतरा में शिक्षक सदन की मांग रखी एवं विधायक दीपेश साहू को मांग पत्र सौंपा। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बसंत कौशिक ने कहा कि शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यों का बढ़ता बोझ उनके मूल दायित्वों को प्रभावित करता है, ऐसे में इस प्रकार के आयोजन शिक्षकों को ऊर्जा, रचनात्मकता एवं संगठनात्मक एकता प्रदान करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर ने सरकार के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों का उल्लेख करते हुए शिक्षकों की मांगों को विधानसभा में रखने हेतु विधायक से प्रतिनिधित्व का आग्रह किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक माननीय दीपेश साहू ने अपने शिक्षक जीवन को भावुकता के साथ स्मरण किया। उन्होंने कहा शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाता, वह जीवन गढ़ता है। मैंने स्वयं शिक्षक के रूप में वह समय जिया है, जब दिन-रात शिक्षा, बच्चों और समाज के भविष्य के बारे में चिंतन चलता रहता है। शिक्षक स्वयं तपकर दूसरों को प्रकाश देने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही वह मजबूत आधार हैं, जिन पर राष्ट्र निर्माण की इमारत खड़ी होती है। शिक्षक सकारात्मक सोच, अनुशासन और सेवा भाव के साथ समाज को दिशा देते हैं। विधायक साहू ने शिक्षकों के जीवन की बारीकियों, उनकी व्यावहारिक समस्याओं और अपेक्षाओं को समझते हुए आश्वस्त किया कि शिक्षकों की हर जायज मांग, हर समस्या और हर सुझाव को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने के लिए मैं पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ता के साथ प्रयास करता रहूँगा।÷उनकी मांग भी मेरी है और उनको पूरा करना मेरा कर्तव्य है। इस अवसर पर विधायक दीपेश साहू ने बेमेतरा में शिक्षक सदन की घोषणा कर शिक्षकों को बड़ी सौगात दी, जिसका उपस्थित शिक्षकों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी जी.आर. चतुर्वेदी ने शिक्षकों से निष्ठा, अनुशासन एवं नवाचार के साथ शिक्षा कार्य करने का आह्वान किया और फेडरेशन के इस प्रयास की सराहना की।

वार्षिक कैलेंडर का विमोचन

इस अवसर पर फेडरेशन द्वारा वार्षिक कैलेंडर का विधिवत विमोचन मंचस्थ अतिथियों द्वारा किया गया तथा शिक्षकों के हित, शिक्षा की गुणवत्ता एवं संगठनात्मक गतिविधियों पर सार्थक चर्चा हुई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र राठौर, अश्वनी कुर्रे (कार्यकारी प्रांताध्यक्ष), बीईओ बेमेतरा कामिनी महिलांग एवं बीआरसी राजेंद्र साहू उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने शिक्षकों के हित में सदैव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में जिले के बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं फेडरेशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से पोखन साहू, गैंदराम वर्मा, बसंत कौशिक, अशोक ध्रुव, चंद्रशेखर पटेल, राजा वर्मा, मनीष पाटिल, सुनील साहू, ओमनारायण साहू, गंगाधर दुबे, बाबूलाल गोयल, हरजीत सिंह अनंत, जय बहादुर राजपूत, ओमप्रकाश कुर्रे, दिलीप पटेल, अजय यादव, नरेश वर्मा।

संक्षिप्त समाचार

सुबह कमरे से नहीं निकली बेटी, फंदे में लटक रही थी लाश

रायपुर। पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोन में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. जब उनके घर की बेटी की लाश कमरे में फांसी के फंदे पर झूलती मिली. मिली जानकारी के अनुसार पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सोन निवासी सुखीराम पटेल की 17 वर्षीय बेटी ईश्वरी पटेल की लाश रविवार की सुबह उसके कमरे में फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली है. परिजनों के अनुसार सभी रात में खाना खाकर सो गए थे. सुबह 6 बजे जब परिजन सो कर उठे तो बेटी ईश्वरी का कमरा बंद था. परिजनों ने आवाज लगाई लेकिन कोई हलचल नही हुई तो खिड़की तोड़कर अंदर झांकते ही उनके होश उड़ गए. उनकी बेटी ईश्वरी पंखे में फांसी के फंदे पर झूल रही थी. जिससे पूरे परिवार में चींख पुकार मच गई. घटना की सूचना पचपेड़ी पुलिस को दी गई, मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को पंचनामा के बाद पीएम के लिए भेज दिया. वही मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है. फ्लिहाल युवती ने आत्महत्या क्यो की इसकी जानकारी सामने नही आई है. परिजनों ने उसकी मानसिक स्थिति ठीक नही होने की जानकारी पुलिस को दी है

एनीकट में नहाने गए दो नाबालिग डूबे, दूसरे दिन रेस्क्यू में मिले शव

रायपुर। जिले के रामनगर स्थित मोहरा एनीकट में नहाने के दौरान दो नाबालिग बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना रविवार दोपहर की है, जब दोनों बच्चे दोस्तों के साथ घूमने के लिए एनीकट पहुंचे थे।नकारी के अनुसार, शिवनंदनपुर निवासी आदिल अंसारी (12 वर्ष), पिता सेराज अंसारी और जयनगर कुंजननगर निवासी अयान सद्दाम (15 वर्ष), पिता मो. जावेद एनीकट में नहाने के लिए उतरे थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते डूब गए।घटना की सूचना मिलते ही डीडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और तलाश अभियान शुरू किया गया। हालांकि, देर शाम तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिल सका। अंधेरा होने और सुरक्षा कारणों के चलते रविवार रात रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया और क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई।सोमवार सुबह दोबारा शुरू किए गए तलाश अभियान में करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने दोनों नाबालिगों के शव बरामद कर लिए। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं इलाके में शोक का माहौल है।

अवैध शराब बेचने वाला पकड़ाया

रायपुर। जिले की कसडोल थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 32 पाव अंग्रेजी व देशी शराब जब्त किया है। उक्त कार्यवाही समाधान सेल में प्राप्त सूचना के आधार पर की गई है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में आमजनों की शिकायत एवं समस्याओं का त्वरित निराकरण करने हेतु जिले में महत्वाकांक्षी योजना समाधान सेल प्रारंभ किया गया है, जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की सूचना, शिकायत अथवा आपराधिक गतिविधि की जानकारी समाधान सेल हेल्पलाइन नंबर 94792 20392 में व्हाट्सएप अथवा कॉल के जरिए प्रदान की जा सकती है। समाधान से के माध्यम से आपराधिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों की धरपकड़ में भी लगातार कामयाबी मिल रही है। इसी तारतम्य में आज दिनांक 08.02.2026 को रात्रि के समय सामाधान सेल में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कसडोल की पुलिस टीम द्वारा ग्राम गोरधा नहर के पास मेनरोड में घेराबंदी कर अवैध रूप से बिक्री करने के लिए शराब ले जाते हुए आरोपी दिनेश कुमार चेलक उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम टेमरी थाना कसडोल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शराब कोचिया से 3330 कीमत मूल्य का 32 पाव अंग्रेजी व्हीस्की/देशी प्लेन शराब एवं अवैध रूप से शराब परिवहन में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 04 एलएस 6047 जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना कसडोल में धारा 34(2) आबकारी के तहत प्रकरण पंजीबध्द कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

गांजा बेचने घूम रहा व्यक्ति पकड़ाया

रायपुर। जिले की मोहन नगर थाना पुलिस ने गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 किलो 30 ग्राम गांजा जप्त किया है। मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 08.02.2026 को थाना मोहन नगर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तितुरडीह दुर्ग क्षेत्र में एक व्यक्ति सफेद रंग के झोले में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करने की फिराक में है। सूचना की तस्दीक हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना मोहन नगर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें उसके कब्जे से 02 किलो 30 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा तथा 22 सौ रूपये नगद बरामद हुआ। पुछताछ में आरोपी ने अपना नाम गोपाल नाग, उम्र 38 वर्ष, निवासी तितुरडीह दुग्र बताया।

प्रदेश में नवाचार, स्टार्ट-अप और कौशल आधारित रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

ज्ञान,तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी देश में विशेष पहचान बनाएगा छत्तीसगढ़

- मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग छत्तीसगढ़ और एसटीपीआई के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता
- आईटी, आईटीईएस एवं इमरजिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा है छत्तीसगढ़

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है।आधुनिक अधोसंरचना, प्रभावी ई-गवर्नेंस प्रणाली और निवेश-अनुकूल नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ आज आईटी, आईटीईएस एवं इमरजिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफइंडिया (एसटीपीआई) के मध्य हुए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवाओं में उद्यमिता विकसित करने और उन्हें आईटी एवं आईटीईएस जैसे क्षेत्रों में विश्वस्तरीय अवसर राज्य के भीतर ही उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल की गई है। इस एमओयू के तहत राज्य में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन एवं औषधीय उत्पाद आधारित मेडटेक, स्मार्ट सिटी समाधान तथा स्मार्ट कृषि जैसे चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो प्रति वर्ष लगभग 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप और एमएसएमई को प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण की सुविधाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस पहल से प्रदेश के युवाओं को राज्य के भीतर ही इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, फंडिंग और आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे उच्च कौशल वाले युवाओं का बड़े शहरों की ओर पलायन रुकेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने एसटीपीआई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्था के सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि देशभर में 68 केंद्रों और 24 सेक्टर-विशेष सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से एसटीपीआई का व्यापक अनुभव छत्तीसगढ़ के स्टार्ट-अप और नवाचार इकोसिस्टम को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह एमओयू राज्य के आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और छत्तीसगढ़ को डिजिटल नवाचार, तकनीकी उद्यमिता और स्टार्ट-अप के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगा।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित फाइलेरिया उन्मूलन अभियान 25 तक

- 18 जिलों में प्रभावितों को दवा खिलाई जाएगी

रायपुर। संवाददाता

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण जो केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष चलाया जाता है इसके तहत दस फरवरी से 25 फरवरी के मध्य फाइलेरिया एवं मलेरिया उन्मूलन अभियान छग के 18 जिलों में एक साथ चलाया जाएगा। उक्त जानकारी प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में कार्यक्रम के संयोजक डॉ. विमल कुमार राय ने दी। राय ने पत्रकारवार्ता में बताया कि फाइलेरिया एवं मलेरिया के समस्य शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। इस वूचेरिया बैकॉप्टी एवं ब्रुजिया मलाई के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि फाइलेनिया रोग का फैलाव रात दस बजे के बाद होता है। इसमें सामान्य मनुष्य को क्यूलेक्स नामक माता मच्छर के काटने से होता है। उक्त रोग चार से पाच वर्ष बाद उचित इलाज नहीं मिलने पर हाथ पाव में तब्दील हो जाता है। डॉ. राय ने बताया कि रायपुर जिले में चार विकास खंड आरंग अभनपुर तिल्दा, धरसींवा एवं रायपुर के शहरीय क्षेत्रों में रामनगर गोगांव,हीरापुर, भनपुरी एवं बिरगांव क्षेत्र में एमडीए किये जाना है। कार्यक्रम का लक्ष्य दवा खाने योग्य जनसंख्या १६१७५२४ रोगियों को दवा खिलानी है। उक्त जिले के लिए बड़ी टीम का गठन किया गया है जिनमें पूरे जिले में ६७९८ दवा खिलाने वाले दल ३३९९ क्षेत्र में लगाये जाएंगे। दवा की खुराग एक से दो वर्ष के बच्चे को डीईसी गोलीनहीं दी जाएगी। जबकि एलबेंडा जोल गोली 400 एमजी आदि खिलाई जाएगी। दो वर्ष से पांच वर्ष के बच्चे को 100 मिग्रा गोली दी जाएगी। जबकि एलबेंडा जोल गोली 400 मिग्रा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को डीईसी गोली 200 मिग्रा और एलबेंडा जोल गोली 400 मिग्रा दी जाएगी।

मामूली विवाद पर पत्नी की डंडे से मार मारकर हत्या,पति गिरफ्तार.....

रायपुर। संवाददाता

जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में सब्जी पकाने की मामूली बात को लेकर हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवति पत्नी की डंडे से मार-मारकर हत्या कर दी औश्र फिर अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला ग्राम ढोठीपहरी, कुरूम ढोढा का है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 06.02.26 को प्रार्थी जेठू विश्वकर्मा उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम बेलसुंगा थाना नारायणपुर के द्वारा थाना नारायणपुर में सूचना दिया गया था कि, उसकी बेटी कमला विश्वकर्मा जो कि चौकी दोकड़ा क्षेत्रांतर्गत ग्राम ढोढ़ीबहार निवासी आरोपी स्वदेश उर्फ सुदेश राम कोरवा से प्रेम करती थी, अत: कुछ वर्ष पूर्व वह, आरोपी स्वदेश उर्फ सुदेश राम कोरवा के पास रहने चली गई थी, आरोपी स्वदेश उर्फ सुदेश राम कोरवा, उसकी बेटी कमला विश्वकर्मा को पत्नी बनाकर रखा था, वर्तमान में दोनों की एक दो वर्षीय बेटी है, व उसकी बेटी कमला विश्वकर्मा 06 माह की गर्भवती थी, करीबन जनवरी माह से प्रार्थी की बेटी कमला व दामाद आरोपी स्वदेश, प्रार्थी के घर ग्राम बेलसुंगा में रह रहे थे, जहां आरोपी स्वदेश ग्राम रनपुर के एक व्यक्ति का ट्रेक्टर को चलता था,। घटना से तकरीबन 01 सप्ताह पूर्व, आरोपी स्वदेश उर्फ सुदेश राम कोरवा अपनी पत्नी कमला विश्वकर्मा व अपनी 02 वर्ष की बेटी को लेकर थाना नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत ही ग्राम ढोठीपहरी, कुरूम ढोढा में अपने नाना के घर लेकर गया था व वहीं रह रहा था। घटना दिनांक 06.02.2026 को शाम करीब साढ़े सात बजे दोनों पति पत्नि के मध्य सब्जी बनाने की बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपी स्वदेश उर्फ सुदेश राम ने आवेश में आकर, पास पड़े डंडे से अपनी पत्नि कमला के साथ मारपीट करते हुए उसके सिर पर वार कर दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अनेक जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।

डीडी नगर में शीघ्र सुन्दर विकसित उद्यानों की सौगात

नागरिको को देने पश्चिम विधायक और महापौर ने किया भूमिपूजन

रायपुर/ संवाददाता

रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड में डीडी नगर सेक्टर 2 उद्यान पहुंचकर प्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत और नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नगर निगम सभापति श्री सूर्यकांत राठौड, एमआईसी सदस्य श्री दीपक जायसवाल श्री भोलाराम साहू, श्रीमती सुमन अशोक पाण्डेय, जोन 5 जोन अध्यक्ष श्री अम्बर अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड पार्षद श्री आशु चंद्रवंशी, पार्षद श्रीमती मीना ठाकुर, पूर्व पार्षद श्री गोपी साहू, श्री रजयंत सिंह ध्रुव, वरिष्ठ पत्रकार श्री शंकर पाण्डेय, ग्रीन आर्मी ऑफ रायपुर के श्री अमिताभ दुबे एवं पदाधिकारीगणों, मंडल अध्यक्ष गुड्डू तिवारी, जिला उपाध्याय नवीन शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री श्रद्धा मिश्रा, जोन 5 जोन कमिश्नर श्री खीरसागर नायक, कार्यपालन अभियंता श्री लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता श्री नागेश रामटेके, महिलाओं, गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, रहवासियों, आमजनो की उपस्थिति में डीडी नगर में 2 उद्यानो के सौंदर्याकरण के कार्य का भूमिपूजन 20 लाख रू. की स्वीकृत लागत से श्रीफल फोड़कर एवं कुदाल चलाकर किया। पूर्व केबिनेट मंत्री रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत ने एजुकेशन हब की जगह मोमोस की दुकान खोले जाने के बाद उक्त स्थान से खाद्य पदार्थो की दुकाने हटाकर वहां नालंदा परिसर पार्ट 2 का कार्य प्रारंभ।

मोदी की गारंटी-भाजपा के घोषणा पत्र को मूर्तरूप देने बनाया जा रहा आगामी बजट

रायपुर। छग विस में बजट सत्र को लेकर सभी तैयारियां शुरू हो गई है। वर्ष 26-27 का बजट फरवरी के 27 तारीख को पेश किये जाने की चर्चा है। इसको लेकर वित्त मंत्रालय में बैठक चल रही है। वित्त सचिव द्वारा इसको लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। राज्य में वर्ष २६-२७ का बजट करीब डेढ़ लाख करोड़ के आसपास का होगा। जिसमें राजकोषीय घाटा सहित अन्य विकासकारी योजनाओं पर फोकस किया जाएगा। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी परंपरानुसार वर्ष २६-२७ का बजट पेश करेंगे। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रांश से अधिक से अधिक अनुदान लेने का प्रयास किया जा रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य में इस समय आय के नये स्रोत ढूंढे जा रहे है लेकिन अभी तक इनमें वृद्धि नहीं हो रहे है। केंद्र द्वारा करेत्तर राजस्व के रूप में एक बड़ी राशि मिलती है। जिसके चलते राज्य का बजट का संचालन हो रहा है। पंचायत, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं गृहविभाग में सबसे ज्यादा राशि आती है।

सूने मकान में चोरी करने वाले मां-बेटे गिरफ्तार....

रायपुर। संवाददाता

कोरबा की थाना कोतवाली पुलिस तथा पुलिस सहायता केंद्र की संयुक्त कार्यवाही में सूने मकान में चोरी करने वाले मां-बेटे को गिरफ्तार किया गया था तथा उनके कब्जे से चोरी कर गिरवी रखे गए सोने-चांदी के आभूषण बरामद किये गये है। बता दें कि कोरबा जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में थाना/चौकी द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस सहायता केंद्र मानीकपुर / थाना कोतवाली कोरबा द्वारा सूने मकान में हुई चोरी की घटना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सफल खुलासा किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 06.02.2026 को प्रार्थी द्वारा चौकी मानिकपुर, कोरबा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह अपने परिवार सहित रायपुर गया हुआ था। दिनांक 07.02.2026 की रात्रि वापस लौटने पर देखा कि उसके घर के बाहर एवं अंदर लगे ताले टूटे हुए थे तथा घर के अंदर रखे सोने-चांदी के जेवरात, नगदी एवं अन्य कीमती सामान चोरी हो चुके थे। प्रारंभिक रूप से चोरी गई संपत्ति की कीमत लगभग 1,80,000 रूपये बताई गई थी। प्रकरण दर्ज कर विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए।

जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने दी आशीर्वाद

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 251 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आज जिले के शहीद शिवकुमार मंडावी खेल मैदान, गोविंदपुर में सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 251 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक कांकेर श्री आशाराम नेताम, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री भरत मटियारा, कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, जिला पंचायत सीईओ श्री हरेश मंडावी सहित जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने नव-दम्पतियों को उनके सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। सामूहिक कन्या विवाह को संबोधित करते हुए विधायक श्री नेताम ने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक सशक्त सहारा है, जो सामाजिक समरसता एवं बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह बहुत अच्छी योजना है, समूह में मिलकर बाजे-गाजे के साथ खुशी भरे माहौल में विवाह सम्पन्न हो रहा है। सभी वर-वधु को सुखी जीवन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने सामूहिक कन्या विवाह में शामिल घराती-बराती का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार की यह महती योजना है। राज्य सरकार द्वारा सामूहिक कन्या विवाह के लिए 35 हजार रूपए की मदद कन्या के उपहार सामग्री के लिए दी जाती है, जो वधु के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाती है। इसके अलावा 01 हजार रूपए परिवहन व्यय के लिए दिए जा रहे हैं। इस प्रकार 36 हजार रूपए की सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। उन्होंने नव-दम्पत्तियों को सुखी वैवाहिक जीवन अपनी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री सामूहिक

कन्या विवाह में 251 जोड़ों का वैदिक रीति-रिवाज के साथ विवाह संस्कार सम्पन्न कराया गया। इनमें कांकेर परियोजना के 43 वर-वधु, चारामा परियोजना के 30, नरहरपुर के 30, भानुप्रतापपुर के 30, अंतागढ़ के 38, दुर्गूकोंदल के 29, कोयलीबेड़ा के 20 और पखांजूर परियोजना 31 वर-वधु शामिल हैं। इस अवसर पर पूर्व सांसद श्री मोहन मंडावी, पूर्व विधायक श्रीमती सुमित्रा मारकोले, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती तेजेश्वरी सिन्हा, जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती तारूणी ठाकुर, श्री सतीश लाटिया, श्री राजीव लोचन सिंह, राजा देवनानी, दिलीप खटवानी, अनूप शर्मा, एसडीएम कांकेर श्री अरूण वर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन सहित नव दम्पत्तियों के परिजन, जनप्रतिनिधि व अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज माँ दंतेश्वरी मंदिर परिसर स्थित मेंढक डोबरा मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माँ दंतेश्वरी को साक्षी मानकर 48 कुंडों में विधिवत मंत्रोच्चार के साथ 191 जोड़े नव दांपत्य जीवन में बंधे। मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ऑनलाइन, वर्चुअल रूप से कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को नव जीवन के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए उनके सुखमय, समृद्ध और खुशहाल दांपत्य जीवन की कामना की।

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट की नजर में क्या है चुनाव आयोग की प्रक्रिया ?

निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठ रहे सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। बिहार से शुरू हुआ विवाद उत्तर प्रदेश से होकर अब पश्चिम बंगाल में केंद्रित हो गया है। पुनरीक्षण प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची से अपात्र लोगों को बाहर करना है, जिनमें स्थान बदलने वाले नागरिक या जिनकी मौत हो चुकी है या फिर गलत तरीके से नाम दर्ज कराने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। चुनाव में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए इस कवायद को जरूरी माना गया है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, मगर इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है पारदर्शिता और निष्पक्षता का। विभिन्न राज्यों में इस प्रक्रिया के तहत मसविदा मतदाता सूची से जितनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम बाहर होने के दावे किए जा रहे हैं, उससे आम नागरिकों के मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। इससे संबंधित मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए आरोप लगाया कि राज्य के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि हर समस्या का समाधान होता है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे। गौरतलब है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें सामने आई हैं कि नागरिकों के नाम मनमाने तरीके से मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए और उन्हें इस संबंध में कारणों की जानकारी भी नहीं दी गई। ऐसे में निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया में मतदाता सूची से बाहर होने वाले लोगों को समय पर सूचित करने और उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के पर्याप्त अवसर देने को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। जाहिर है, अगर पुनरीक्षण को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने को प्राथमिकता दी जाती, तो संभवत: अनावश्यक विवाद खड़े नहीं होते। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश दिया था कि इस पूरी प्रक्रिया में तार्किक विसंगतियों की श्रेणी में रखे गए मतदाताओं का सत्यापन पारदर्शी ढंग से होना चाहिए, ताकि इससे नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा या तनाव न हो। आयोग को तार्किक विसंगति सूची में नामों का उल्लेख करने के कारणों को तत्काल सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि संबंधित व्यक्ति यह जान सके कि गड़बड़ कहां हुआ है और उसमें अपेक्षित सुधार किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि राज्य में नाम, उपनाम या आयु में गड़बड़ी को लेकर अब तक 1.36 करोड़ लोगों को तार्किक विसंगतियों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

उक्त वर्णित मुक्त व्यापार समझौता विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। इसके पूर्व, सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते के रूप में चीन एवं 10 आशियान देशों के बीच सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते को माना जाता है। यह केवल एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन के 27 देशों एवं भारत के बीच साझा समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट है। दिनांक 27 जनवरी 2026 को यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों के साथ भारत ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। अब, इस समझौते की शर्तों को इन देशों की संसद द्वारा पारित किया जाएगा, इसके बाद यह मुक्त व्यापार समझौता यूरोपीय यूनियन एवं भारत के बीच होने वाले विदेशी व्यापार पर लागू हो जाएगा। इस मुक्त व्यापार समझौते को 'मदर आफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है।

भारत वसुधैव कुटुम्बकम के भाव के साथ मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न कर रहा है

(प्रह्लाद सबनानी)

क्योंकि, यह मुक्त व्यापार समझौता विश्व के 28 देशों के उस भूभाग पर लागू होने जा रहा है, जहां विश्व की 30 प्रतिशत आबादी निवास करती है। पृथ्वी के इस भूभाग पर 200 करोड़ से अधिक नागरिकों का निवास है। इन 28 देशों की संयुक्त रूप से विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी (संयुक्त रूप से) अर्थव्यवस्था (यूरोपीय यूनियन - 22 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर) एवं चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (भारत - 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर) के बीच यह मुक्त व्यापार समझौता सम्पन्न होने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर होने वाले विदेशी व्यापार में इन समस्त देशों की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत है। पूरी दुनिया में 33 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी व्यापार होता है, इसमें से 11 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी व्यापार उक्त 28 देशों द्वारा किया जाता है।

उक्त वर्णित मुक्त व्यापार समझौता विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। इसके पूर्व, सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते के रूप में चीन एवं 10 आशियान देशों के बीच सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते को माना जाता है। यह केवल एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन के 27 देशों एवं भारत के बीच साझा समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट है। इस समझौते में पूरी दुनिया की आर्थिक दशा एवं दिशा बदलने की क्षमता है। उक्त व्यापार समझौता को सम्पन्न करने के प्रयास पिछले 18 वर्षों से हो रहे थे। परंतु, कुछ विपरीत परिस्थितियों के चलते इस समझौते को सम्पन्न होने में इतना लम्बा समय लग गया है, अतः यह अब भारत एवं यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। उक्त मुक्त व्यापार समझौते के सम्पन्न होने के पश्चात वर्ष 2032 तक यूरोपीयन यूनियन के सदस्य देशों एवं भारत के बीच विदेशी व्यापार के दुगना होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इसके पूर्व भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच भी मुक्त व्यापार समझौता सम्पन्न किया जा चुका है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री भी संभवत: मार्च माह में भारत के दौरे पर आने वाले है और भारत एवं कनाडा के बीच भी कुछ क्षेत्रों में व्यापार समझौता सम्पन्न होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। अमेरिका मुक्त व्यापार समझौतों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है ताकि भारत एवं अन्य समस्त देशों में निवासरत नागरिकों को इन समझौतों से लाभ मिले। यह भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुम्बकम के भाव को दर्शाता है। भारत की इस नीति के चलते ही विश्व के कई देश अब भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते शीघ्र ही सम्पन्न करना चाह रहे हैं। वैश्विक स्तर पर हाल ही के समय में आर्थिक क्षेत्र में भारी उथल पुथल दिखाई दे रही है। भारत एवं यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों के बीच सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते से इस उथल पुथल में कुछ सुधार आता हुआ दिखाई देगा। भारत में कृषि एवं डेयरी क्षेत्र अतिसंवेदनशील है। क्योंकि, भारत की कुल आबादी का लगभग 60 प्रतिशत भाग आज भी ग्रामीण इलाकों में उक्त क्षेत्रों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। अतः उक्त

दोनों क्षेत्रों को मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखा गया है। हां, भारत के समुद्री उत्पाद उद्योग, वस्त्र एवं परिधान उद्योग, जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग, चमड़ा उद्योग, खिलौना उद्योग जो श्रम आधारित उद्योग हैं, को उक्त मुक्त व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ होगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन के समस्त 27 देशों द्वारा भारत से उक्त उत्पादों के आयात पर आयात ड्यूटी को शून्य किया जा रहा है। वर्तमान में भारत से समुद्रीय उत्पादों के निर्यात पर 26 प्रतिशत का आयात कर लगाया जाता है, जिसे मुक्त व्यापार समझौता के लागू होने के पश्चात शून्य कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, वस्त्र एवं परिधान के आयात पर वर्तमान में लागू 12 प्रतिशत के आयात कर को शून्य किया जा रहा है, खिलौना पर लागू 4.7 प्रतिशत के आयात कर को शून्य, जेम्स एवं ज्वेलरी के आयात पर 4 प्रतिशत से शून्य, केमिकल उत्पादों के आयात पर 12.8 प्रतिशत से शून्य, चमड़ा से निर्मित उत्पादों के आयात पर 17 प्रतिशत से शून्य, फर्नीचर उत्पादों के आयात पर 10.7 प्रतिशत से शून्य आयत कर किया जा रहा है।

यूरोपीय यूनियन के 27 देश, जो विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हैं, में जन्म दर पिछले कई वर्षों से लगातार गिर रही है एवं कुछ देशों में तो यह शून्य के स्तर पर पहुंच गई है जिससे इन देशों में प्रौढ़ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले नागरिकों का इन देशों में नितांत अभाव दिखाई देता है। अतः इन देशों में श्रमबल की भारी कमी है। उक्त मुक्त व्यापार समझौते के सम्पन्न होने के पश्चात भारतीय नागरिकों को यूरोपीय यूनियन के समस्त 27 देशों में तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, आदि में रोजगार के भारी मात्रा में अवसर प्राप्त होंगे। इन समस्त देशों द्वारा भारतीय नागरिकों को वीजा प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। युनाईटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रान्स आदि जैसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे देशों में भारतीय इंजिनीयरों एवं डाक्टरों की भारी मांग है। उक्त देशों द्वारा भारतीयों के परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने के अवसर भी प्रदान करने सम्बंधी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। भारतीय विद्यार्थियों द्वारा यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरांत 9 माह से 12 माह तक का समय रोजगार तलाशने के लिए प्रदान किया जाएगा। इस समयावधि तक भारतीय युवाओं को इन देशों में प्रवास की अनुमति प्रदान की जाएगी।

भारतीय कारीगरों के लिए अब वैश्विक बाजार खुल रहा है। साथ ही, भारत अब विनिर्माण इकाईयों का वैश्विक केंद्र बन सकता है। क्योंकि, यूरोपीयन यूनियन के समस्त देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हैं एवं वे अपनी सम्पत्ति/पूंजी का निवेश भारत में विनिर्माण इकाईयों में कर सकते हैं एवं कुछ लाभप्रद क्षेत्रों में वे अपनी विनिर्माण इकाईयों की स्थापना भी कर सकते हैं। अधिक उत्पादन इकाईयों की स्थापना से भारत में रोजगार के अधिक अवसर भी निर्मित होंगे। इससे भारत में बेरोजगारी की समस्या का हल भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।

भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को इस दृष्टि के साथ सम्पन्न किया जा रहा है ताकि इससे भारत के किसान, मजदूर, कारीगर, पेशेवर नागरिकों एवं सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्योगों को विशेष लाभ हो। यूरोपीयन यूनियन के समस्त 27 देशों में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र का आकार 26,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है, इससे भारत से वस्त्र एवं परिधान का निर्यात वर्तमान में 64,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इसी प्रकार, चमड़ा उत्पादों का बाजार 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है एवं जेम्स एवं ज्वेलरी का बाजार 7,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। 27 देशों में इस विशाल क्षेत्र में भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग एवं अन्य उत्पादों को प्रवेश मिलने से भारत में श्रम आधारित कई सूक्ष्म, छोटी एवं मध्यम इकाईयों को लाभ होने जा रहा है। लगभग इसी प्रकार का लाभ अन्य क्षेत्रों यथा, समुद्री उत्पाद, चमड़ा उत्पाद, खिलोना उत्पाद, जेम्स एवं ज्वेलरी उत्पाद, केमिकल उत्पाद, फर्नीचर उत्पाद आदि, में कार्यरत इकाईयों की भी होने जा रहा है। इन क्षेत्रों में कार्यरत विनिर्माण इकाईयों के व्यापार में वृद्धि का आश्य सीधे सीधे अधिक श्रमबल की आवश्यकता होना भी है, जिसकी पूर्ति आज विश्व में केवल भारत ही कर सकता है।

रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। इस क्षेत्र में भारत का अंतिम लक्ष्य आत्मनिर्भरता हासिल करने का है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन द्वारा यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों को सुरक्षा के सम्बंध में अमेरिका पर निर्भर नहीं रहते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह दी है। अतः यूरोपीय देश अपने सुरक्षा बजट में अत्यधिक वृद्धि करने का विचार कर रहे हैं। भारत के लिए ऐसे समय पर उक्त मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाना एक सुनहरे अवसर के रूप में सामने आया है। इससे सुरक्षा के क्षेत्र में उत्पादन कर रही भारतीय कम्पनियों को यूरोपीय यूनियन का अति विशाल बाजार मिलने जा रहा है। इसी के साथ ही यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों से सुरक्षा के क्षेत्र में उच्च तकनीकी का हस्तांतरण भारतीय कम्पनियों को सम्भव हो सकेगा। कुल मिलाकर यूरोपीय यूनियन के समस्त 27 देशों के साथ सम्पन्न किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते से भारत के लिए अतिलाभप्रद स्थिति बनने जा रही है। (लेखक सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक)। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

आम बजट 2026-27 से होगा समावेशी विकास, विकसित बनेगा भारत

(मनोज गोयल)

केंद्रीय बजट भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम प्रतीत होता है। दरअसल, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत बनाए रखने के लिए जो निर्णायक कदम उठाए हैं, उससे देश के विकास को रफ्तार मिलेगी।

राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा ने अमृत काल में विकसित भारत के दृष्टिगत विगत एक दशक से जारी अनवरत समावेशी विकास के तहत एनडीए सहयोगियों को भरोसे में लेकर जिस प्रकार से आम बजट 2026-27 को प्रस्तुत किया, उसमें आरएसएस की जनोन्मुखी सोच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासी दूरदर्शिता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आर्थिक शिल्पकारिता का सटीक संदेश मिलता है। इससे विगत 12 वर्षों से जारी चतुर्दिक विकास को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, और सियासी संसारमें मजबूत भारत का डंका बजेगा। भारत अब अमेरिका और चीन से प्रतियोगिता करेगा और राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम से अगले दशक तक उन्हें भी मात देगा। दुनियादारी के विशेषज्ञों की टिप्पणियों से भी इस बात की तस्दीक की जा सकती है।

आम बजट 2026-27 साफगोई पूर्वक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की नीतियों और सुशासन की निरंतरता को रेखांकित करता है। यह केंद्रीय बजट भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम प्रतीत होता है। दरअसल, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत बनाए रखने के लिए जो निर्णायक कदम उठाए हैं, उससे देश के विकास को रफ्तार मिलेगी। चूंकि जनता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भरोसा करती है, इसलिए उसकी समग्र बेहतरी के लिए लाया हुआ यह युवा बजट हरेक दृष्टि जनकल्याणकारी है।

वर्तमान बजट में समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ खास जरूर है, जिससे सबका साथ, सबका विकास जैसी लोकतांत्रिक जनभावना को जनविश्वास हासिल होता है और सरकार को मजबूती मिलती है। सरकार ने कोशिश की है कि युवाओं, किसानों, महिलाओं, कामगारों, उद्यमियों और बुजुर्गों के निजी व सार्वजनिक हितों का संबर्धन होता रहे। मौजूदा बजट हमारे लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की प्रगति करता है, देश में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में काम करने वालों के उज्ज्वल भविष्य को मजबूत बनाता है, नए रोजगार और कौशल बढ़ाता है, जिससे निश्चय ही विकास की गति तेज होगी। इसलिए मैं इस बजट को विकसित भारत 2047 के स्वर्णिम भविष्य के लिए तैयार युवा बजट कहूंगा। क्योंकि यह वास्तव में एक ऐसा बजट है जो भारत की जरूरत और लक्ष्य को हासिल करने की नींव रखता है।

जैसा कि हमारे दिग्गज नेताओं ने एक स्वर से कहा भी है कि यह आम बजट देश और इसकी जनता के अरमानों को पंख लगाता है, जिससे गरीब, युवा और बेरोजगार सबको आगे बढ़ने के सुनिश्चित साधन मिलते हैं। चूंकि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास और भरोसा करती है, इसलिए बजट का मुख्य उद्देश्य विकास और प्रगति दोनों है, क्योंकि इसमें देश और उसकी जनता की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाया गया है।इसके सभी प्रावधान आम जनता के लिए ही बनाए गए हैं। इसलिए आम बजट 2026-27 विकास और प्रगति पर केंद्रित बजट है। जिससे देश के लोग खुश हैं। इस बजट की सियासी आलोचना के अलावा अन्य की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे मोदी है तो मुमकिन है, का भाव और मजबूत हुआ है।

भविष्य में भारत को और अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए सरकार के संकल्प को दर्शाता है। जब महज 12 वर्षों के भाजपा और राजग शासनकाल में भारत, अमेरिका और चीन को रणनीतिक कूटनीतिक स्वायत्तता जैसी टक्कर देने की स्थिति में पहुंच चुका है तो अगले 10 वर्षों और खासकर विकसित भारत 2047 तक भारत की अंतरराष्ट्रीय हैसियत क्या होगी, समझना मुश्किल नहीं है। (लेखक भाजपा नेता व पूर्व पार्षद हैं)। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

जेफ्री एपस्टीन की फाइल से उठे सवालों के जवाब जानकर आपका हैरान होना पक्का है

जेफ्री एपस्टीन पहले ही यौन अपराधों में दोषी ठहराया जा चुका था। वर्ष 2008 में उसे सजा मिली, पर वह कड़े दंड से बच गया। वर्ष 2019 में उसे फिर नाबालिग लड़कियों की तस्करी जैसे गंभीर आरोपों में पकड़ा गया, लेकिन मुकदमा पूरा होने से पहले ही वह जेल में मृत पाया गया। अमेरिका के न्याय विभाग ने जब जेफ्री एपस्टीन से जुड़े लाखों पन्नों के कागजात सार्वजनिक किये, तो दुनिया भर में हलचल मच गयी। इन दस्तावेजों में कई देशों के बड़े नेताओं, धनवान लोगों और प्रभावशाली हस्तियों के नाम संदर्भ के रूप में सामने आये, जिससे राजनीति और कूटनीति दोनों में गरमाहट बढ़ गयी। हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा है कि किसी का नाम आना अपराध का प्रमाण नहीं है।

(नीरज कुमार दुबे)

इन खुलासों ने वैश्विक स्तर पर बहस और सनसनी का माहौल बना दिया है। हम आपको बता दें कि जेफ्री एपस्टीन पहले ही यौन अपराधों में दोषी ठहराया जा चुका था। वर्ष 2008 में उसे सजा मिली, पर वह कड़े दंड से बच गया। वर्ष 2019 में उसे फिर नाबालिग लड़कियों की तस्करी जैसे गंभीर आरोपों में पकड़ा गया, लेकिन मुकदमा पूरा होने से पहले ही वह जेल में मृत पाया गया। उसकी मौत को आधिकारिक रूप से आत्महत्या बताया गया, पर उसके संपर्कों का जाल दुनिया भर में फैला होने से संदेह और चर्चा का दौर कभी थमा नहीं।

नये कागजातों में अनेक देशों के प्रभावशाली लोगों के साथ उसके संदेश, मुलाकातें और संपर्क दर्ज हैं। अमेरिका के बड़े राजनेताओं, उद्योगपतियों और तकनीकी जगत के धनाढ्यों तक के नाम सामने आये हैं। पर हर जगह एक ही चेतावनी दोहरायी गयी है कि संदर्भ का अर्थ दोष सिद्धि नहीं है।

भारत के संदर्भ में सबसे अधिक चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर हुई। कागजातों में कुछ संदेश कथित रूप से ऐसे हैं जिनमें उद्योगपति अनिल अंबानी और एपस्टीन के बीच बातचीत में भारत के प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं और मुलाकातों का जिक्र है। इन संदेशों में अमेरिका और इजराइल से जुड़ी कूटनीतिक पहल पर चर्चा दिखती है। हम आपको याद दिला दें कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा ऐतिहासिक मानी गयी थी, क्योंकि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी।

इन संदेशों में यह भी दिखता है कि अनिल अंबानी ने कुछ मौकों पर अमेरिकी सत्ता से जुड़े लोगों से संपर्क साधने में मदद की बात कही। एपस्टीन ने भी अपनी शेखी भरी भाषा में लिखा था कि उसकी सलाह कारगर रही। पर यह

सब उसके निजी दावे हैं, जिनका कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं दिया गया। भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री की आधिकारिक इजराइल यात्रा के अलावा बाकी बातें एक दोषी व्यक्ति की बेबुनियाद बकवास हैं और उन्हें उसी तरह खारिज किया जाना चाहिए। सरकार ने दो टूक कहा कि बिना आधार की अटकलों को सच की तरह फैलाना गैर जिम्मेदाराना है।

इसी बीच विपक्ष, खासकर कांग्रेस, ने सवाल उठाये और पारदर्शिता की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री को स्वयं सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जो किसी गैर कानूनी काम की ओर सीधा संकेत करे। हम आपको यह भी बता दें कि इन कागजातों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी आया है। उनके और एपस्टीन के बीच निवेश और भारत में अवसरों को लेकर संदेशों का आदान प्रदान दिखता है। इस पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उनके सभी संपर्क केवल औपचारिक थे।

भारत से बाहर देखें तो नॉर्वे की युवरानी मेटे मारित के एपस्टीन से लंबे समय तक संपर्क के संकेत मिले हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से खेद जताया और कहा कि यह उनका गलत निर्णय था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रुड का नाम एपस्टीन की मुलाकात सूची में दर्ज बताया गया, हालांकि उन्होंने किसी भी नजदीकी संबंध से इंकार किया है। ब्रिटेन के वरिष्ठ नेता पीटर मैंडलसन को लेकर भुगतान और संपर्क की बातें सामने आयीं, जिनके बाद उन्हें राजनीतिक आलोचना झेलनी पड़ी और पद छोड़ना पड़ा। स्लोवाकिया के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाजचाक ने तो विवाद बढ़ने पर इस्तीफा तक दे दिया, भले ही उन्होंने आरोपों को नकारा। वहीं कुछ धनकुबेर जैसे एलन मस्क और बिल गेट्स के साथ संदेशों के आदान प्रदान ने यह दिखाया कि एपस्टीन प्रभावशाली लोगों के बीच पहुंच बनाने में माहिर था। पर हर मामले में वही सावधानी दोहरायी गयी कि संपर्क या संदेश अपने आप में अपराध सिद्ध नहीं करते, फिर भी इन खुलासों ने दुनिया भर में सत्ता और धन के रिश्तों पर असहज सवाल खड़े कर दिये।

हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा जेफ्री एपस्टीन से जुड़े लगभग पैंतीस लाख नये दस्तावेज जारी किये जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी फिर से चर्चा में आ गया है। हालांकि शुरुआती सरकारी बयान और उपलब्ध कागजात यह संकेत देते हैं कि ट्रंप के खिलाफ किसी यौन अपराध या आपराधिक कृत्य का सीधा प्रमाण इन फाइलों में नहीं मिला है, फिर भी उनके और एपस्टीन के संबंधों को लेकर सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं।

न्याय विभाग के उप महान्यायवादी टॉड ब्लांश ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि एपस्टीन के वर्षों के पत्राचार की समीक्षा के बाद ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें एपस्टीन ने ट्रंप पर कोई आपराधिक आरोप लगाया हो या पीड़ितों के साथ ट्रंप के अनुचित संबंध का जिक्र किया हो। उन्होंने यहां तक कहा कि जब एपस्टीन ने ट्रंप की बुराई करने की कोशिश भी की, तब भी उसने कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया। यह बयान साफ तौर पर ट्रंप को संभावित राजनीतिक नुकसान से बचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

लेकिन दस्तावेजों को विस्तार से देखने पर तस्वीर थोड़ी जटिल लगती है। ट्रंप का नाम कुछ अपुष्ट सूचनाओं में आया है जो जांच एजेंसी को भेजी गयी थीं। एक पीड़िता के साक्षात्कार के हस्तलिखित नोट्स में भी उनका नाम दर्ज है। एपस्टीन के एक कर्मचारी ने जांचकर्ताओं से कहा कि उसे याद है कि ट्रंप कभी एपस्टीन के घर आये थे। साथ ही वर्ष 2002 के कुछ संदेशों में मेलानिया नाम की महिला द्वारा दोस्ताना संवाद और पाम बीच यात्रा का जिक्र मिलता है। ये संदर्भ सीधे तौर पर अपराध साबित नहीं करते, पर संबंधों की प्रकृति पर जिज्ञासा जरूर बढ़ाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप प्रशासन ने लंबे समय तक इन फाइलों को सार्वजनिक करने में अनिच्छा दिखाई, जबकि चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप पारदर्शिता की बात करते रहे थे। ट्रंप ने अपने ऊपर लगे एक आरोप को लेकर एक बड़े अखबार पर मुकदमा भी किया, जिसमें दावा था कि उन्होंने एपस्टीन के लिए आपत्तिजनक चित्र और टिप्पणी भेजी थी। इन फाइलों में ट्रंप के करीबी लोगों के नाम भी सामने आये हैं। हॉवर्ड लटनिक के परिवार सहित एपस्टीन के द्वीप जाने की योजना का जिक्र है, हालांकि उन्होंने मुलाकात से इंकार किया है। एलन मस्क के संदेशों में एपस्टीन के द्वीप और पार्टियों में रुचि दिखती है, भले ही यात्रा साकार न हुई हो। स्टीव बैनन और एपस्टीन के बीच लंबा संवाद और एक विस्तृत वीडियो साक्षात्कार का भी उल्लेख है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप सभी एपस्टीन फाइलें जारी करवाएंगे? हालांकि अमेरिकी न्याय विभाग संकेत दे चुका है कि हालिया जारीकरण उनके प्रयासों का लगभग अंत है। दूसरी ओर कुछ सांसदों का कहना है कि अभी लाखों पन्ने रोके गये हैं और उन्हें सार्वजनिक होना चाहिए। लेकिन घरेलू राजनीति यहां निर्णायक भूमिका निभा सकती है। पूरी फाइलें जारी करने से कई प्रभावशाली लोगों के नाम और संदर्भ खुल सकते हैं, जिसका राजनीतिक असर व्यापक होगा। ऐसे में संभावना यही दिखती है कि पारदर्शिता और राजनीतिक नुकसान के बीच संतुलन साधने की कोशिश चलेगी। ट्रंप फिलहाल सीधे आरोपों से बचे दिखते हैं, पर अधूरी जानकारी और रोके गये दस्तावेज यह बहस जिंदा रखेंगे कि क्या सच का पूरा हिस्सा अभी सामने आना बाकी है। इन सबके बीच तरह तरह की कहानियां भी चल पड़ी हैं। कुछ लोग हर नाम को अपराध का प्रमाण मान रहे हैं, तो कुछ इसे बड़ी साजिश बताकर प्रचारित कर रहे हैं। स्पष्ट है कि एपस्टीन प्रकरण ने सत्ता, धन और प्रभाव के रिश्तों पर सवाल जरूर खड़े किये हैं, पर हर नाम को दोषी ठहराना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। देखा जाये तो एपस्टीन प्रकरण में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कागजातों में संदर्भ मात्र को भी अपराध की मुहर की तरह पेश किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति न्याय और विवेक दोनों के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो शोर मचाया गया, वह इसी राजनीति का उदाहरण लगता है। एक दोषी व्यक्ति के निजी संदेशों में कही गयी शेखी को ऐसे उछाला गया मानो वही अंतिम सत्य हो। यह पूछने की जरूरत किसी ने नहीं समझी कि क्या कोई आधिकारिक प्रमाण है, क्या कोई जांच है, क्या कोई आरोप पत्र है। केवल नाम जोड़कर बदनाम करने की कोशिश हुई। हम हर सनसनी पर बह जाएं तो कल कोई भी कहानी हमारे विवेक को बंधक बना लेगी। इसलिए जरूरी है कि हम नाम नहीं, प्रमाण देखें; आरोप नहीं, सत्य खोजें। तभी न्याय भी बचेगा और लोकतंत्र भी।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

मॉडल हॉस्टल घोषित करने की उठी मांग, प्रशासन के लिए बना अध्ययन का विषय

नक्सल छाया से निकलकर शिक्षा की रोशनी तक : डोलेरास बालक आश्रम बना बदलाव की मिसाल

सुकमा/छिंदगढ़। कभी नक्सल गतिविधियों के लिए पहचाना जाने वाला ग्राम डोलेरास अब शिक्षा, अनुशासन और सांस्कृतिक चेतना की नई पहचान गढ़ रहा है। बालक आश्रम डोलेरास का वार्षिकोत्सव केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उस सामाजिक परिवर्तन का जीवंत प्रमाण बना, जो वर्षों की सतत मेहनत और प्रतिबद्धता से संभव हुआ है। वार्षिकोत्सव के दौरान बच्चों की प्रस्तुतियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भय और असुरक्षा के साए से निकलकर यह क्षेत्र अब आत्मविश्वास और भविष्य निर्माण की ओर अग्रसर है। नृत्य, नाट्य एवं कविताओं के माध्यम से बच्चों ने शिक्षा, सामाजिक समरसता और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद मंच से यह संदेश उभरकर सामने आया कि यदि विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, तो सबसे कठिन क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव संभव है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य अधिवक्ता दीपिका शोरी ने आश्रम की व्यवस्थाओं को जिले के लिए अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा– मैं पिछले दस वर्षों से यहां आ रही हूं। डोलेरास बदला है, लेकिन इस आश्रम की व्यवस्थाएं हमेशा सशक्त रही हैं और लगातार बेहतर होती गई हैं। उन्होंने आश्रम अधीक्षक शेषमणी दुबे की प्रशंसा करते हुए कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहते हुए भी उन्होंने बच्चों के भविष्य से कभी समझौता नहीं किया। आश्रम की व्यवस्थाएं आज पूरे जिले के लिए उदाहरण हैं। दीपिका शोरी ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि आश्रम का निरीक्षण कर इसे 'मॉडल हॉस्टल' घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे सामाजिक समरसता का प्रतीक बताते हुए कहा कि बिना किसी भेदभाव के एक आदिवासी आश्रम का सफल संचालन पूरे समाज के लिए सीख है।

बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा— आप यहां सिर्फ पढ़ने और आगे बढ़ने आए हैं। आपको इतना सशक्त बनना है कि हर वर्ग के बच्चों से आगे निकलें। कार्यक्रम को जिला पंचायत सदस्य हूँगाराम,अन्नू मंडावी एवं बुधराम ने भी सम्बोधित किया। सोरी, बनसिंह बेलसरिया, अवकेश सिंह, कपिल कुमार निराला, तुलसी राम कश्यप, रमेश निषाद, अजीत दिवाकर, मनेश गावड़े, हरा ठाकुर, दुर्गेश कुमार बंजारा, राजेंद्र कुमार आगरे एवं लिखेशर साहू उपस्थित रहे।

प्रस्तुति एवं आयोजन में सहयोग देने वाले – राहुल, कृष्णा, सुरेश, संतु, सावन, लोकेश, लखन, मिथिलेश, उमेश, हूंगा, अमित यादव, रवि मुचाकी, मंगल मरकाम, महावीर मुचाकी, लखीराम बघेल, प्रभाष सोढ़ी, आयुष सोढ़ी, आयता मांडवी, गौरव मरकाम, हरीश कश्यप, सुरेश यादव, संतु यादव, राहुल करटामी, इंद्र नाग, कृष्ण यादव, उमेश ताती, हूंगा मरकाम, उत्म दूधो, सुभाष मांडवी, कोसा मुचाकी, हिडमा पोडियामी, लखमा कवासी, देवा मुचाकी, लखेश्वर नाग, राजू कुंजाम, टंकेश्वर यादव, संदीप बारसे एवं सागर पोडियामी का विशेष योगदान रहा।

कोंटा बीईओ विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, छह सप्ताह में फैसले का निर्देश

कोंटा। कोंटा विकासखंड के बहुचर्चित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीईओ पद को लेकर उठे विवाद ने अब प्रशासनिक दायरे से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर याचिका के बाद यह मामला अचानक सुर्खियों में आ गया है और जिले भर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। शिक्षा विभाग के भीतर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है, जिससे आने वाले दिनों में बड़ा फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के पांच प्राचार्यों द्वारा न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें जूनियर अधिकारी के पद पर बने रहने को चुनौती दी गई। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का स्पष्ट निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश ने प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी और बढ़ा दी है, वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बेचैनी साफ देखी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सवाल केवल सीनियरिटी या विभागीय नियमों का नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक समीकरणों की भी चर्चा जोरों पर है। स्थानीय स्तर पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस नियुक्ति में सत्ता पक्ष के नेताओं की पसंद- नापसंद भी प्रभाव डाल सकती है, या फिर पूरी प्रक्रिया सिर्फ नियमों और वरिष्ठता के आधार पर ही तय होगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी पक्ष खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह मुद्दा तेजी से तूल पकड़ता दिख रहा है। विभागीय सूत्रों की मानें तो कई दावेदार इस पद की दौड़ में शामिल हैं और सभी की नजर अब जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। कुछ नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो चुपचाप अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे बताए जा रहे हैं। सीनियरिटी, अनुभव और प्रशासनिक रिकॉर्ड तीनों ही पहलुओं को लेकर अंदरखाने मंथन जारी है। वही विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक पद की नियुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर सकता है। यदि निर्णय निष्पक्ष और समयबद्ध नहीं हुआ तो इसका असर विभागीय मनोबल के साथ-साथ राजनीतिक माहौल पर भी पड़ सकता है। फिलहाल कोंटा में यह मुद्दा चाय चौपाल से लेकर सरकारी दफ्तरों तक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर प्रशासन किस आधार पर फैसला करेगा और क्या इस निर्णय में केवल नियमों की भूमिका होगी या फिर राजनीतिक इच्छाशक्ति भी परदे के पीछे असर डालेगी। आने वाले छह सप्ताह कोंटा की प्रशासनिक और राजनीतिक दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं।

खूनी जमीन विवाद : प्राणघातक हमले में गई जान, पुलिस ने दोनों भाइयों को भेजा जेल

केशकाल। केशकाल थाना क्षेत्र के ग्राम गारका में जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। जहां फेंसिंग को लेकर हुए विवाद के दौरान दो सगे भाइयों ने मिलकर पड़ोसी प्रदीप सिन्हा पर लोहे के सब्बल से प्राणघातक हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल प्रदीप सिन्हा को इलाज के लिए तत्काल रायपुर रेफर किया गया। जहां 8 फरवरी की देर रात उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

ये है पूरा मामला– पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 फरवरी को प्रार्थिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया था कि उसके पति प्रदीप सिन्हा अपने घर-बाड़ी में मजदूरों के माध्यम से फेंसिंग के लिए तार व खुटा लगा रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले सुंदर लाल सिन्हा और किशुन सिन्हा वहां पहुंचे और जमीन पर फेंसिंग लगाने को लेकर विवाद करने लगे। दोनों ने एक राय होकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान सुंदर लाल सिन्हा ने प्रदीप सिन्हा के पैर पकड़ लिए, जबकि किशुन सिन्हा ने लोहे के सब्बल से सिर पर प्राणघातक वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल प्रदीप सिन्हा को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केशकाल ले जाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया था। प्रार्थिया की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 296 एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देश पर थाना प्रभारी विकास बघेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुंदर लाल सिन्हा (60 वर्ष) एवं किशुन सिन्हा (58 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम गारका को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरी. विकास बघेल, उपनिरीक्षक कंवल सिंह शोरी सहित थाना केशकाल की पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा।

भानुप्रतापपुर में वन विभाग की भूमि पर 'पट्टा' आवंटन में बड़ा खेल, पटवारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

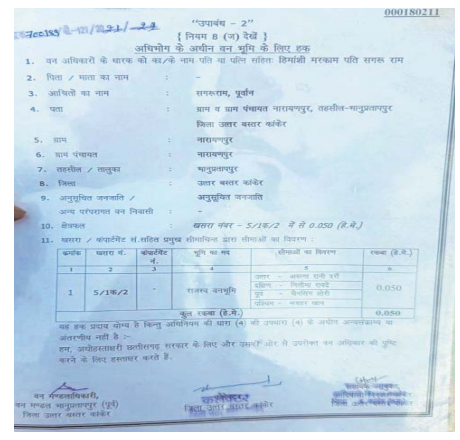

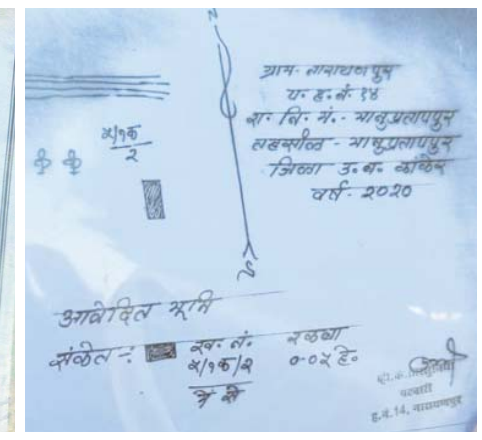

भानुप्रतापपुर । भानुप्रतापपुर क्षेत्र में वन विभाग की बेशकीमती भूमि पर फर्जी तरीके से वन अधिकार पत्र पटटा जारी करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि राजस्व पटवारी ने नियमों को ताक पर रखकर और आर्थिक लाभ लेकर अपात्र व्यक्तियों के नाम पर नक्शा-खसरा जारी कर दिया, जिसके आधार पर उनके पटटे भी बन गए हैं।

वन भूमि पर राजस्व विभाग की 'सेंधमारी' – शिकायत के अनुसार, पूरा मामला वन भूमि कक्ष क्रमांक पीएफ 827 का है। नियमानुसार यह भूमि पूर्णतः वन विभाग के अधीन है और इस पर किसी भी प्रकार के राजस्व हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके, पूर्व में पदस्थ रहे राजस्व पटवारी विशेष तिरसुनिया द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया गया।

2005 की शर्त का उल्लंघन और फर्जीवाड़ा – शिकायतकर्ता यशवंत चक्रधारी ने दस्तावेजों के साथ उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। आरोप है कि 'वन अधिकार अधिनियम 2006' के प्रावधानों के अनुसार, केवल उन्हीं व्यक्तियों को पट्टा मिल सकता है जो 2005 से पूर्व से उस भूमि पर काबिज हों। लेकिन पटवारी विशेष तिरसुनिया ने कथित तौर पर मोटी रकम लेकर उन लोगों को भी 2005 से पूर्व का निवासी बता दिया, जो वास्तव में उस समय वहां काबिज ही नहीं थे।

इन 8 लोगों को मिला 'संदिग्ध' लाभ – शिकायत पत्र में उन लाभार्थियों की सूची भी सौंपी गई है, जिनके पटटों की जांच की मांग की गई है। उर्मिला सोरी, शिवबति दुग्गा, ओमबती, हेमंत सोनी, प्रेमलता दर्रो, दरबार सिंह, रामेश्वरी, हिमांशी मरकाम शामिल है। जिनका पटावरी द्वारा नक्सा खसरा जारी कर पटटा बनने के लिए दस्तावेज तैयार किया गया है जिसके बाद इनका पट्टा बन गया।हैं।

जिला दंडाधिकारी व मुख्य वन संरक्षक से उच्च स्तरीय जांच की मांग – मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता ने जिला दंडाधिकारी कांकेर, मुख्य वन संरक्षक सहायक आयुक्त और पूर्व वन मंडलाधिकारी भानुप्रतापपुर को लिखित शिकायत सौंपी है और पटवारी विशेष तिरसुनिया द्वारा जारी किए गए नक्शा-खसरा की उच्च स्तरीय जांच हो।

नियमों के विरुद्ध जारी किए गए पट्टों को तत्काल निरस्त किया जाए। दोषी पटवारी और संलिप्त अन्य लोगों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही की जाए। वर्तमान में वन विभाग और प्रशासन के पास शिकायत पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि सरकारी जमीन और नियमों के साथ हुए इस खिलवाड़ पर प्रशासन क्या सख्त कदम उठाता है।

ऋषभ जैन- डीएफओ पूर्व वन मंडल भानुप्रतापपुर – वन विभाग के जमीन का पटवारी द्वारा कैसे नक्सा खसरा जारी किया गया है इसके जांच के लिए एसडीओ को जांच करने के लिए पत्र जारी किया गया है। जांच होने के बाद संबंधित पटवारी के ऊपर कार्यवाही किया जाएगा।

समूचे छत्तीसगढ़ व बस्तर के विकास में उड़ान के लिए बजट : श्रीनिवास राव मद्दी

बीजापुर। समूचे छत्तीसगढ़ व बस्तर के विकास में उड़ान के लिए बजट ने केन्द्र सरकार के बजट को नवोत्थान और वैश्विक भारत की प्रतिष्ठापना वाहक बताया और कहा कि इस बार के बजट में सिर्फ आँकड़े ही नहीं हैं, बल्कि विकसित भारत-2047 का विजन भी सामने रखा गया है। आगे मद्दी ने बजट प्रावधानों की सराहना की और इसे केवल एक वार्षिक वित्तीय विवरण न मानकर देश के अगले 25 वर्षों के विकास का मार्गदर्शक 'विजन डॉक्यूमेंट' बताया। श्रीनिवास राव मद्दी एक महत्वपूर्ण तथ्य साझा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के बस्तर खनन-सम्रद्ध जिलों को सीधा लाभ बताया आगे कहा कि यह बजट तीन विशेष कर्तव्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाएंगे। इस बजट में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकार किया गया है, जिसकी योजनाएँ आगामी 5 वर्षों के लिए महत्वपूर्ण दिशा तय करेंगी। मद्दी ने विश्वास जताया कि बजट में निर्धारित लक्ष्यों के माध्यम से देश बिजली, बुनियादी ढांचे और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति करेगा। यह बजट समावेशी विकास की ओर बढ़ता हुआ एक सशक्त कदम है। इस दौरान जिलाध्यक्ष घासीराम नाग, जिला महामंत्री संजय लुक्कड़, फूलचंद गागड़ा, जिला उपाध्यक्ष गोपाल सिंह ठाकुर, एसटी मोर्चा प्रदेश मंत्री,जिला राम राना, मडल अध्यक्ष अशोक राव,पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जागर लक्षमैय्या उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष बने संजय राय

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ की प्रदेश समिति द्वारा नियुक्त पाँच सदस्यीय तदर्थ टीम की उपस्थिति में नारायणपुर जिला इकाई का गठन किया गया। इस अवसर पर जिले के संरक्षक सुनील सिंह राठौर, पूर्व जिलाध्यक्ष मो. इमरान खान एवं उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से संजय राय को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई।

इसके साथ ही संघ की जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। जिसमें महेश पाठक, महेंद्र कुमार, सुनील सिंह राठौर, शिवकुमार पांडे, एवं मो. इमरान खान को संरक्षक नियुक्त किया गया। वहीं नितेश गोस्वामी एवं रामप्रकाश सोनटेके को उपाध्यक्ष, शेख मेहमुद्दीन को महामंत्री तथा नवेंद्र नागवंशी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा मो. रफीक, विजय राज मिश्रा, नवीन जैन, विश्वनाथ दुग्गा एवं राजकुमार बघेल को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया। जिले की कमान संभालते हुए नवनियुक्त जिलाध्यक्ष संजय राय ने कहा कि वे संघ की गरिमा बनाए रखते हुए संगठन को सशक्त बनाने तथा निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. निजामी, तदर्थ समिति सदस्य अनिल अग्रवाल, इंदर कोटवानी, मनोज गोस्वामी, विजय लांगड़े, विश्वजीत मल्लिक, पूर्व अध्यक्ष मो. इमरान खान, संरक्षक सुनील सिंह राठौर, शेख मेहमूद, नितेश गोस्वामी सहित जिले के अनेक पत्रकारगण उपस्थित रहे।

प्राण घातक हमला करने वाले दो सगे भाई गिरफ्तार

कोंडागांव। ग्राम गारका के थाना केशकाल में प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसके पति प्रदीप सिन्हा अपने घर बाडी में मजदूर लगाकर फेसिंग के लिए तार खुटा लगा रहे थे उसी समय गांव के पडोस के रहने वाले सुन्दरलाल सिन्हा, किशुन सिन्हा आये और हमारे जमीन में क्यो फेसिंग के लिए तार खुटा लगा रहे हो कहकर एक राय होकर मॉ बहन की अश्लील गन्दी गन्दी गाली गलौच कर तुम्हे जान से मार देगें कहकर सुन्दर लाल सिन्हा इसके पति प्रदीप सिन्हा के दोनो पैर को जमकर पकडा था तथा आरोपी किशुन सिन्हा के द्वारा लोहे के सब्बल से जान से मारने की नियत से इसके पति के सिर में प्राण घातक हमला कर चोट पहुंचाया है। जिससे प्रार्थिया की पति प्रदीप सिन्हा को सिर में चोट लगकर घायल होने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केशकाल लायें जहां उसकी बेहतर उपचार के लिए रायपुर रिफर किया गया था।

कलेक्टर ने किया छात्र दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत दिवंगत छात्र के परिजन को बीमा राशि का चेक प्रदाय

नारायणपुर । कलेक्टर नम्रता जैन ने छात्र दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत शासकीय बालक बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गरांजी, नारायणपुर में कक्षा आठवीं में अध्ययनरत दिवंगत छात्र स्व. सुनील नेताम के परिजनों को बीमा राशि का चेक प्रदान किया। छात्र स्व. सुनील नेताम, पिता सन्तुराम नेताम, निवासी घोटियामुंडा चांदाबेड़ा, विकासखण्ड फरसगांव, जिला कोण्डागांव का 13 सितंबर 2025 को छात्रावास में आकस्मिक निधन हो गया था। उक्त दुखद घटना के पश्चात छात्र दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण की गई। 09 फरवरी को कलेक्टर नम्रता जैन द्वारा दिवंगत छात्र के पिता सन्तुराम नेताम को 1 लाख रुपये की बीमा राशि का चेक प्रदाय किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार पटेल सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

वटकेश्वर महादेव मंदिर का मनाया जा रहा है तृतीय स्थापना दिवस

किरन्दुल। किरन्दुल वार्ड क्रमांक 07 पुराना भट्टी पारा स्थित वटकेश्वर महादेव मंदिर की तृतीय स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा हैं। इस दो दिवसीय आयोजन के प्रथम दिवस मंदिर प्रांगण से श्री राघव मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई।जिसमें किरन्दुल नगरपालिका अध्यक्ष रूबी शैलेन्द्र सिंह,वार्ड पार्षद बी रूपा रानी, अन्य पार्षदगण सहित मातृशक्तियां, बच्चें युवा एवम वयस्क भारी संख्या में सम्मिलित हुए। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कल 10 फरवरी मंगलवार सुबह रुद्राभिषेक एवं हवन पूजन किया जाएगा। तत्पश्चात दोपहर 01 बजे महाभण्डारे का आयोजन रखा गया हैं।

उच्च शिक्षा आयुक्त ने रामकृष्ण मिशन आश्रम में नए कॉलेज खोलने के लिए किया निरीक्षण

नारायणपुर । जिले में उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण पहल करते हुए उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन के नारायणपुर आगमन पर अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस. आर. कुंजाम तथा प्राध्यापक भगवान दास चांडक एवं राजेंद्र कुमार यादव ने उनका स्वागत किया। डॉ. देवांगन ने जिले के महाविद्यालयों की उपलब्धियां और चुनौतियों पर चर्चा की, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत चल रहे हैं शैक्षणिक सुधारो पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें लगातार स्वयं को अद्यतन रखना चाहिए। जीवन में सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और जो व्यक्ति समय के साथ अपने ज्ञान और कौशल को अपडेट करता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। इस अवसर पर रामकृष्ण मिशन आश्रम में आगामी सत्र 2026-27 में महाविद्यालय खोलने के लिए मूलभूत जानकारी एवं चिन्हित स्थलों का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने आधारभूत संरचना, भूमि की उपलब्धता, शैक्षणिक वातावरण एवं विभिन्न बिंदुओं पर गहन मूल्यांकन किया निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी चाहते हैं कि बस्तर में ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वे यहीं से रोजगार प्राप्त करें। जिले में नए महाविद्यालय की स्थापना से न केवल विद्यार्थियों को विविध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के अधिक मौके मिलेंगे और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। उच्च शिक्षा विभाग का यह प्रयास बस्तर के नारायणपुर जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। इस दौरान रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के सचिव, स्वामी व्यासानंद जी महाराज एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित हुए।

संक्षिप्त समाचार

बिलासपुर संभाग के शाखा डाकघरों में मिल रही सभी प्रमुख डाक सेवाएं

बिलासपुर। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शाखा डाकघरों में डाक विभाग से संबंधित लगभग सभी आवश्यक कार्य सुचारू रूप से संपादित किए जा रहे हैं। इन शाखा डाकघरों के माध्यम से आम जनता को उनके निवास स्थान के समीप ही डाक सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो रही है। शाखा डाकघरों में पत्रों की बुकिंग, प्रेषण एवं वितरण के साथ-साथ बचत बैंक खाते खोलने, जमा-निकासी, डाक जीवन बीमा तथा अन्य जन-उपयोगी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इससे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को भी डाक सेवाओं का पूर्ण लाभ मिल रहा है। डाक विभाग का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सरल, सुलभ और विश्वसनीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। डाकघर अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी शाखा डाकघर अथवा उप डाकघर से संपर्क कर विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

संभाग स्तरीय रोजगार मेला 12 एवं 13 फरवरी को, 26 निजी कंपनियों द्वारा 4 हजार पदों पर होगी भर्ती

बिलासपुर। राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 12 एवं 13 फरवरी को सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक आईटीआई कोनी में संभाग स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। 26 निजी कंपनियों द्वारा फायनेंस, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, मेडिकल व फार्मेसी, सोलर एनर्जी, टेक्सटाईल इंडस्ट्री, सर्विस टेक्निकल, मेनुफैक्चरिंग, सिक्यूरिटी सर्विस, इंश्योरेंस, आटोमोबाईल, ज्वेलेरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 4 हजार पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए रोजगार पंजीयन, ई रोजगार पोर्टल में आवेदक का ऑनलाईन मेला पंजीयन होना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक आधार कार्ड, फोटो, बायोडाटा एवं निर्धारित शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ रोजगार मेले में शामिल हो सकते है। मेले में शामिल होने एवं रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी 222.द्दह्शद्भद्दड्डह्.ष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ एवं छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप से प्राप्त कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय कोनी से भी संपर्क किया जा सकता है।

देह व्यापार का भंडाफोड़, होटल से 3 महिलाएं संचालक और होटल मैनेजर गिरफ्तार

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन में जिले में देह व्यापार के विरुद्ध अभियान स्तर पर सख्त कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में शहर के होटल ट्रिनिटी की सातवीं मंजिल में संचालित सनराइज स्पा एंड सैलून में अवैध देह व्यापार संचालित होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना पर एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा द्वारा थाना कोतवाली एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर योजनाबद्ध तरीके से करीब शाम 7:30 बजे रेड कार्यवाही की गई। कार्यवाही के तहत पहले एक पाइंटर को ग्राहक बनाकर रुपये देकर स्पा सेंटर भेजा गया। पाइंटर से संकेत प्राप्त होते ही पुलिस टीम ने होटल में दबिश दी। छापेमारी के दौरान होटल के तीन अलग-अलग कमरों में तीन महिलाएं मिलीं। महिलाओं की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों द्वारा कमरों की तलाशी ली गई, जहां आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। पूछताछ में स्पा सेंटर संचालक विनयकांत बरगट ने स्वीकार किया कि ग्राहकों को आकर्षित करने एवं अवैध कमाई के उद्देश्य से लड़कियां उपलब्ध कराई जाती थीं। पुलिस द्वारा होटल मैनेजर देवेन्द्र सिंह को भी हिरासत में लेकर थाना लाया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक ओप्पो रेनो 11 प्रो 5त्र मोबाइल, नगदी 6,000 रुपये(पुलिस पाइंटर द्वारा दिया हुआ), स्पा सेंटर से संबंधित दस्तावेज, ग्राहकों का रजिस्टर एवं किरायानामा (वर्ष 2024 से) जप्त किया है।

सरकारी स्कूलों में ढाई लाख बच्चों को मिड-डे-मील में मिलेगा महुआ लड्डू

कोरबा । जिले के सरकारी प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले करीब ढाई लाख बच्चों को अब महुआ का लड्डू भी दिया जाएगा। इस नई पहल का उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। योजना के तहत वन विभाग छह वनधन विकास केंद्र के माध्यम से फूड ग्रेड महुआ की खरीदी करेगा और इसे महिला स्व-सहायता समूहों को निशुल्क उपलब्ध कराएगा। महिला समूह महुआ से लड्डू तैयार कर शिक्षा विभाग को आपूर्ति करेंगे। लड्डू सप्ताह में एक दिन मिड डे मील के साथ वितरित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। जंगल के वनोपज का अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है।

परीक्षा के 3 घंटे जीवन का भविष्य तय नहीं करते

धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ बिना डरे दें परीक्षा-कलेक्टर

बिलासपुर। जिला प्रशासन, यूनिसेफ एवं छत्तीसगढ़ अग्रिकॉन समिति के संयुक्त तत्वावधान में हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के तहत आयोजित परीक्षा पर चर्चा में कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन कर हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में स्कूलों के बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और कलेक्टर के प्रेरक विचारों को सुना। दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में जिले के लगभग 37 हजार बच्चे शामिल हो रहे है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि 20 एवं 21 फरवरी से कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह वर्षभर की मेहनत के आकलन का समय है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने नियमित अध्ययन किया है, उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को तैयारी में कमी महसूस हो रही हो तो घबराने के बजाय धैर्य और संयम के साथ पढ़ाई करें। जिन विषयों में पकड़ मजबूत है, उन्हें प्राथमिकता दें तथा नियमित रूप से रीविजन करें। उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा को जीवन का अंतिम निर्णय न मानने की सलाह देते हुए कहा कि किसी एक परीक्षा से व्यक्ति की संपूर्ण काबिलियत तय नहीं होती। दुनिया में अनेक उदाहरण हैं, जहां लोगों ने पारंपरिक शिक्षा पूरी न करने के बावजूद अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर, थॉमस एडिसन, धीरूभाई अंबानी, स्टीव जॉब्स और कपिल शर्मा जैसे व्यक्तित्वों का उल्लेख करते हुए कहा कि आत्मविश्वास, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा के तीन घंटे जीवन का संपूर्ण भविष्य निर्धारित नहीं करते। यह समय धैर्य, अनुशासन और संयम बनाए रखने का है। विद्यार्थियों को प्रतिदिन कम से कम 40 मिनट शारीरिक व्यायाम करने, सकारात्मक मित्र समूह बनाने तथा समूह चर्चा के माध्यम से अध्ययन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चर्चा के माध्यम से पढ़ी गई सामग्री अधिक समय तक स्मरण रहती है। कठिन विषयों की नियमित अभ्यास से समझ मजबूत होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने विद्यार्थियों को देश का जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ते समय माता-पिता के सपनों और अपेक्षाओं को सदैव स्मरण रखें। यदि किसी परीक्षा का परिणाम अपेक्षित न आए तो निराश होने के बजाय अगली परीक्षा के लिए और बेहतर तैयारी करें। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने गैजेट्स से दूरी बनाए रखने, समय प्रबंधन तथा मानसिक एकाग्रता जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका कलेक्टर ने सरल एवं व्यावहारिक सुझावों के साथ जवाब दिया। सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान अनावश्यक तनाव से बचें, पर्याप्त नींद लें तथा मानसिक शांति बनाए रखें। सकारात्मक सोच और संतुलित दिनचर्या से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री शिव कुमार बनर्जी तथा समग्र शिक्षा के जिला मिशन समन्वयक श्री ओम पांडे उपस्थित रहे।

फाइलेरिया संक्रमण से बचाव हेतु कलेक्टर ने स्वयं दवा सेवन किया और लोगों को किया प्रेरित.......

गौरेला पेंड्रा मरवाही। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत फाइलेरिया (हाथीपांव) संक्रमण से बचाव हेतु सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के तहत कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने आज जिला चिकित्सालय में स्वयं दवाई का सेवन किया और लोगो को भी अनिवार्य रुप से दवा का सेवन करने प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे, प्रभारी अपर कलेक्टर अमित बेक, एसडीएम पेण्ड्रारोड विक्रांत अंचल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा एवं चिकित्सालय के स्टाफउपस्थित रहे। सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम जिले में 25 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस अभियान के तहत 12 फरवरी तक सभी स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्रों में बूथ लगाकर दवा का वितरण किया जाएगा। 13 से 22 फरवरी तक दवा प्रशासकों द्वारा घर-घर जाकर योग्य व्यक्तियों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। किसी कारणवश छूटे हुए व्यक्तियों को 23 से 25 फरवरी तक दवा का सेवन कराया जाएगा। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु जिले में कुल 671 दल तैनात किए गए हैं। कार्यक्रम की निगरानी के लिए 149 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक योग्य व्यक्ति को एल्बेंडाजोल, डीईसी एवं आइवरमेक्टिन की दवा का सेवन कराया जाएगा।

विज्ञान में महिलाओं और बच्चों की भूमिका पर विशेष कार्यक्रम आयोजित

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। मिश्री देवी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गौरेला में 'विज्ञान में महिलाओं और बच्चों की भूमिका' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना तथा विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्य उषा शर्मा ने की। अपने संबोधन में उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज महिलाएं विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान, चिकित्सा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि विज्ञान केवल एक विषय नहीं, बल्कि नवाचार, तर्कशीलता और समाज निर्माण का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर छात्राओं अंशिका मिश्रा, मोनिका यादव, शिवानी यादव और ज्योति भैना ने अंतरिक्ष अनुसंधान, चिकित्सा विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण एवं तकनीकी विकास जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। छात्राओं ने देश-विदेश की महिला वैज्ञानिकों के योगदान और नई वैज्ञानिक खोजों की जानकारी साझा कर उपस्थित जनों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में शिक्षिका तान्या गुप्ता एवं शारदा अग्रवाल ने भी छात्राओं को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और वैज्ञानिक सोच अपनाने पर बल दिया। जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने अपने संदेश में कहा कि विज्ञान में महिलाओं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है,।

बिलासपुर में जनहित के विषयों को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं नगर विधायक अमर अग्रवाल विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए....

बिलासपुर। अमर अग्रवाल ने स्वामी आत्मानंद महारानी लक्ष्मी बाई शासकीय बहुउद्देशीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, बिलासपुर के वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होकर प्रतिभाशाली छात्राओं को सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षित और संस्कारित बेटियाँ ही सशक्त समाज एवं विकसित भारत की आधारशिला हैं। इसके पश्चात वे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरकंडा के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए, जहाँ छात्राओं को सम्मानित करते हुए उन्होंने बालिका शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। इसी क्रम में अमर अग्रवाल भाजपा कार्यालय, बिलासपुर में आयोजित पार्षद दल की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में शहर के विभिन्न वार्डों से संबंधित मूलभूत समस्याओ एवं अन्य नागरिक सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अमर अग्रवाल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल समस्याएँ उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने पार्षदों से वार्डवार समस्याओं का संकलन कर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार करने का आग्रह किया तथा जनहित के प्रत्येक विषय को संबंधित विभागों तक प्रभावी रूप से पहुँचाकर समाधान की दिशा में निरंतर प्रयास करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही रेलवे क्षेत्र स्थित बंगाली स्कूल में आयोजित शाला उन्नयन एवं प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में भी वे शामिल हुए। इसके अतिरिक्त मोपका स्थित गृह प्रवेश कार्यक्रम में सहभागिता कर उन्होंने परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

सिक्किम से 15-सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने किया गेवरा खदान का भ्रमण

■ हरित, सुरक्षित और आधुनिक कोयला खनन प्रक्रियाओं को नज़दीक से देखा

बिलासपुर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) सिक्किम एवं छत्तीसगढ़, के संयुक्त तत्वधान में सिक्किम से 15-सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 10 फरवरी 2026 को एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा का दौरा किया। यह दौरा देश की ऊर्जा सुरक्षा में एसईसीएल भूमिका, पर्यावरणीय प्रयासों और सतत खनन पहलों को प्रत्यक्ष रूप से समझने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा में अत्याधुनिक एचईएमएम संचालन का अवलोकन किया। मीडिया दल को सरफेस माइनर के माध्यम से ब्लास्ट-फ्री कोयला उत्खनन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई, जो पर्यावरण-अनुकूल होने के साथ-साथ सुरक्षित और प्रभावी खनन का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधिमंडल ने फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के माध्यम से की जा रही पर्यावरण-अनुकूल कोयला डिस्पैच प्रणाली को भी देखा, जिससे धूल-उत्सर्जन में कमी, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है। इसके साथ ही गेवरा में विकसित मियावाकी पद्धति से किए गए सघन पौधारोपण को भी मीडिया सदस्यों ने सराहा। पत्रकारों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब उन्होंने कोयला खनन कार्यों को इतनी नज़दीक से देखा। उन्होंने देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण के प्रति एसईसीएल के संतुलित दृष्टिकोण की सराहना की। गेवरा दौरे के उपरांत प्रतिनिधिमंडल ने एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर में एसईसीएल प्रबंधन से श्री एन फ्रैंक्लिन जयकुमार, निदेशक (तक.) संचालन, श्री बिरंची दास, निदेशक (एचआर), श्री रमेश चन्द्र महापात्र, निदेशक (तक.) योजना/परियोजना- के साथ संवाद किया, जहाँ संगठन की भावी योजनाओं, सतत विकास लक्ष्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों पर विस्तार से चर्चा हुई।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के राष्ट्रीय कार्यशाला में एसईसीएल की 'डिजीकोल' पहल बनी पारदर्शी सुशासन का मॉडल........

बिलासपुर। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 11 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पहल 'डिजीकोल को सार्वजनिक उपक्रमों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने वाली एक आदर्श डिजिटल पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया। कार्यशाला में एसईसीएल की ओर से मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री हिमांशु जैन ने विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि डिजीकोल पहल के माध्यम से खनन कार्यों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डिजिटल निगरानी और डेटा आधारित प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ रूप से लागू किया गया है, जिससे संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। डिजिटल निगरानी से मजबूत हुआ संचालन तंत्र प्रस्तुति के दौरान विभिन्न तकनीकी पहलों की जानकारी दी गई— एमईएमएम फ्लीट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से शॉवेल, डंपर एवं डोजर जैसे भारी खनन उपकरणों की रियल-टाइम ट्रैकिंग की जा रही है। सेंसर आधारित प्रणाली से उपकरणों की लोकेशन, ऑपरेटिंग ऑवर्स और ईंधन खपत की निगरानी होती है। ईंधन में असामान्य गिरावट, अनावश्यक निष्क्रिय समय तथा निर्धारित मार्ग से विचलन की स्वतः पहचान संभव हो पाई है। वीडियो एनालिटिक्स एवं कनेक्टेड वर्कर सिस्टम के जरिए सुरक्षा प्रबंधन, परिचालन नियंत्रण तथा आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। ड्रोन आधारित सर्वेक्षण से अतिक्रमण की पहचान, हॉल रोड एवं ढलानों की निगरानी तथा मानसून के दौरान जल निकासी व्यवस्था के आकलन में सटीकता आई है। डेटा-ड्रिवन माइन प्लानिंग एवं अनुकूलित ड्रिलिंग-ब्लास्टिंग प्रणाली ने उत्पादन प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक एवं सटीक बनाया है। इसके साथ ही डिजिटल भूमि अभिलेख, ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म, स्पेयर प्रबंधन प्रणाली एवं डिजिटल वॉर रूम जैसी पहलों ने एक एकीकृत एवं छेड़छाड़-रोधी (टैम्पर-प्रूफ) डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया है। मुख्यालय में हुआ लाइव वेबकास्ट-इस अवसर पर एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर में कार्यशाला के वेबकास्ट का सामूहिक अवलोकन किया गया। सीएमडी एसईसीएल श्री हरीश दुहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुति में सहभागिता की। उनके साथ निदेशक (तकनीकी-संचालन) श्री एन. फ्रैंक्लिन जयकुमार, निदेशक (कार्मिक) श्री बिरांची दास, निदेशक (वित्त) श्री डी. सुनील कुमार, निदेशक (तकनीकी-परियोजना एवं योजना) श्री रमेश चंद्र मोहापात्रा सहित मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान-राष्ट्रीय मंच पर डिजीकोल की प्रस्तुति स्श्वष्टरु की डिजिटल परिवर्तन यात्रा को मिली महत्वपूर्ण मान्यता है। यह उपलब्धि न केवल कोयला क्षेत्र में स्श्वष्टरुकी अग्रणी भूमिका को रेखांकित करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता को सुदृढ़ करते हुए राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार जिम्मेदारी और दक्षता के साथ की जा सकती है।

त्वचा को स्वस्थ बनाने के लिए ध्यान देना बेहद जरूरी

त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि आप स्किन केयर का हर स्टेप सही तरह से फॉलो करें। फिर चाहे फेस को मॉइस्चराइज करना हो या फिर फेस क्लींजिंग और टोनिंग हो। इसका पहला स्टेप होता है फेस को वॉश करना और अगर आप इसी में मिस्टेक करते हैं तो इसके बाद वाले सारे स्किन केयर स्टेप का पूरा फायदा नहीं मिलता है। ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि दिन में दो या तीन बार फेस वॉश किया जा सकता है या फिर लोग फेस वॉश खरीदने के दौरान उसके इन्ग्रेडिएन्ट्स और स्किन टाइप का ध्यान रखते हैं, लेकिन फेस को धोने के दौरान भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स ज्यादातर लोग करते हैं। फेस वॉश करने के बाद स्किन बहुत ड्राई हो जाती है या फिर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी रूखापन बना रहता है। आपके फेस वॉश का सही रिजल्ट त्वचा पर नहीं दिख रहा है तो इसके पीछे आपकी ही कुछ गलतियां होती हैं जो आप चेहरा धोने के दौरान या फिर इसके बाद करते हैं। चलिए जान लेते हैं इस बारे में डिटेल के साथ।

सूखी स्किन पर फेस वॉश लगाना

बहुत सारे लोग हाथ पर फेस वॉश निकालते हैं और सीधे चेहरे पर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये गलती आपकी त्वचा को और ज्यादा ड्राई बना सकती है। फेस वॉश लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से गीला कर लें। इससे फेस वॉश त्वचा पर सही तरह से फैल जाता है और अच्छी तरह से फेस क्लीन होता है। जबकि सूखी त्वचा पर फेस वॉश लगाने से वो सही से नहीं फैलता और उस जगह पर ज्यादा लगा रहता है जहां आपने सबसे पहले अप्लाई किया हो और त्वचा का उतना हिस्सा थोड़ा ड्राई हो सकता है।

ज्यादा या कम फेस वॉश लेना

बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनको कितना फेस वॉश लेना है। कई बार लोग ढेर सारा फेस वॉश लगा लेते हैं, क्योंकि उनके लगता है कि इससे त्वचा ज्यादा अच्छी तरह साफ होगी तो कई बार लोग स्किन ड्राई होने के डर से कम फेस वॉश लगाते हैं। सबसे सही तरीका है कि आप रुपये के सिक्के के बराबर अपने हाथ पर फेस वॉश लें और इसे चेहरे पर अप्लाई करें।

जल्दी चेहरा धो लेना

अक्सर लोग चेहरे पर फेस वॉश लगने के बाद हाथों से एक दो बार मसाज करते हैं और फिर चेहरा धो देते हैं, लेकिन अगर सैलिसिलिक एसिड वाला या फिर नियासिनामाइड वाला फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं,तो इसमें मौजूद इन एक्टिव इनग्रेडिएंट्स को वर्क करने का टाइम नहीं मिलता है, जिससे आपके फेस पर असर दिखाई नहीं देता है।

ज्यादा ठंडा या गर्म पानी यूज करना

फेस वॉश करने के लिए लोग सीधे टैंक के पानी का यूज कर लेते हैं जो सर्दी के दिनों में बेहद ठंडा होता है। ये आपकी त्वचा के साथ ही हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसी तरह से बहुत ज्यादा गर्म पानी का यूज करने से त्वचा ड्राई हो जाती है। चेहरे को हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से ही धोना चाहिए।

घर की इस दिशा में बैठकर करें काम

करियर में होगी तरक्की

वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर का हर एक कोना और दिशा बेहद महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि अगर घर में चीजें वास्तु के मुताबिक ना रखी हों, तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच कलह, विवाद और तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यहां तक अगर हम गलत दिशा में भी बैठकर घर में काम करें, तो इसका असर आपको करियर पर पड़ता है। क्योंकि आज भी बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम कर रहे हैं। आजकल इसका ट्रेंड बढ़ गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में काम करने के लिए सही दिशा का चुनाव करने से न केवल आपके करियर की प्रगति होती है, बल्कि आप मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में भी सक्षम होते हैं। चलिए जानते हैं कि किस दिशा में बैठकर काम करना चाहिए।

इन बातों का रखें ध्यान

बहुत से लोग अपने बेडरूम में काम करते हैं। वास्तु के मुताबिक ऐसा कर ना अशुभ होता है। इससे सुस्ती आती है। संभव हो तो अलग कमरा या कोना चुनें। ध्यान रखें कि हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर चेहरा करके बैठें।

सही दिशा

यह दिशा कुबेर और सफलता की वास्तु की मानें, तो घर में काम करने के लिए उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा सबसे उत्तम है। य मानी जाती है। इसके अलावा पूर्व और उत्तर दिशा वर्क फ्रॉम होम के लिए सबसे शुभ मानी जाती हैं। वहीं, काम के लिए जो मेज यानी डेस्क इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए। गोल या टेढ़ी-मेढ़ी मेज से बचें। बैठते समय ध्यान रखें कि आपकी पीठ के पीछे ठोस दीवार हो, खिड़की नहीं। यह स्थिरता प्रदान करता है।

लैपटॉप या गैजेट्स को कहां रखें

ज्यादातर लोग घर से काम करने के लिए लैपटॉप और अन्य गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सवाल उठता है कि इसे किस दिशा में रखना चाहिए। वास्तु की मानें, तो मेज के दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) हिस्से में रखना सही माना जाता है। इससे फोकस बढ़ता है और काम में मन लगता है।

बालों का झड़ना रोकेगा ये देसी हेयर ऑयल

सर्दियों का मौसम जहां एक ओर सुकून लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर बालों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है। ठंडी हवा, कम नमी और स्कैल्प का ड्राई हो जाना बालों की जड़ों को कमजोर बना देता है जिससे हेयर फॉल बढ़ने लगता है और ग्रोथ रुक जाती है। कई लोग इस दौरान महंगे हेयर प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स लंबे समय में बालों को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे सबसे सुरक्षित और असरदार विकल्प बनते हैं।

हेयर ग्रोथ ऑयल के लिए जरूरी सामग्री

सरसों का तेल, सफेद तिल, कलौंजी (Nigella Seeds), मेथी दाने, कुटी हुई अदरक- ये सभी सामग्री बालों की ग्रोथ बढ़ाने, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और डैंड्रफ कम करने में मदद करती हैं।

कैसे बनाएं?

एक पैन में सरसों का तेल लें और उसमें सफेद तिल, कलौंजी, मेथी दाने और कुटी हुई अदरक डालें। अब इसे धीमी आंच पर तब तक उबालें, जब तक तेल का रंग हल्का गहरा ना हो जाए। आंच बंद करके तेल को ठंडा होने दें और फिर छानकर किसी कांच की बोतल में भर लें।

कैसे करें इस्तेमाल?

रात में सोने से पहले इस तेल से स्कैल्प में हल्के हाथों से मसाज करें। तेल को पूरी रात लगा रहने दें और अगली सुबह माइल्ड शैम्पू से धो लें। हफ्ते में 2–3 बार इसका इस्तेमाल करने से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं।

हेयर ऑयल के फायदे

सरसों का तेल स्कैल्प को गर्म रखता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। मेथी दाने हेयर फॉल कम करते हैं और नए बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। कलौंजी बालों को मजबूत बनाकर समय से पहले सफेद होने से बचाती है। अदरक स्कैल्प में सूजन और डैंड्रफ कम करने में मदद करता है। सफेद तिल बालों को पोषण देकर उन्हें घना और चमकदार बनाते हैं।

हरी मिर्च को महीनों तक स्टोर करने का नुस्खा

सर्दियों में हरी मिर्च खूब सारी मिलती है। जब भी सब्जी खरीदने जाएं तो कुछ मिर्ची तो फ्री में ही मिल जाती है। जिसे लापरवाही से रखा जाए तो जल्दी ही सड़ना शुरू कर देती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन फ्री की मिल रही हरी मिर्च को स्टोर कर रख सकते हैं। जिससे ना केवल आपको फ्रेश मिर्ची का टेस्ट मिलेगा बल्कि आपके पैसे भी बचेंगे। तो बस सीख लें हरी मिर्ची को महीनों तक चलाने का आसान नुस्खा।हरी मिर्च का फ्रेश टेस्ट पसंद है तो इसे पेस्ट बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लें। ये महीनों तक खराब नहीं होंगे और फ्री में मिलने वाली हरी मिर्ची भी आसानी से यूज हो सकेगी।

बस सारी हरी मिर्ची की डंठल को निकालकर अलग कर लें और मिर्ची को धो लें। अब इन सारी हरी मिर्ची को साफ कपड़े से सुखा लें, जिससे कि इनका पानी सूख जाए।बस मिर्चियों को काटकर छोटा कर लें और मिक्सी के जार में डाल दें। साथ ही नमक और नींबू का रस डालें और पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को किसी साफ-सुथरे और सूखे कांच के जार में भर लें। जब पेस्ट को जार में भर लें तो सबसे ऊपर कुछ बूंदे तेल की जरूर डाल दें। तेल मिर्ची के लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा और खराब होने से बचाएगा। बस मिर्ची के पेस्ट पर डेट का लेबल चिपकाकर फ्रिज में स्टोर कर लें। महीनों तक ये पेस्ट खराब नहीं होगा और आराम से यूज करें।

हरी मिर्च को फ्रिज में स्टोर करने का तरीका

फ्रिज में हरी मिर्च रखने के बाद भी सड़ जाती है या सूख जाती है तो उसे महीनों तक फ्रेश बनाकर रखने के लिए इस टिप्स को फॉलो करें। हरी मिर्ची को धोकर सुखा लें। फिर किसी साफ-सूखे प्लास्टिक के डिब्बे पर साफ कॉटन के कपड़े को रखें और उसमे इन मिर्चियों को रखकर ढक्कन से बंदकर फ्रिज में डाल दें।

अमरूद खाने के फायदे

सर्दियों में अमरूद खूब मिलते हैं और एक्सपर्ट हमेशा सीजनल फ्रूट खाने की सलाह देते हैं। लेकिन अमरूद को काफी सारे लोग नापसंद करते हैं। जबकि इसमे काफी ढेर सारे न्यूट्रिशन होते हैं। जो वेट लॉस, डायबिटीज, हार्ट हेल्थ से लेकर पाचन को सही करने में मदद करते हैं।

एक अमरूद में एक संतरे के मुकाबले चार गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। तो अगर आप अमरूद को डाइट में शामिल करते हैं तो इतने सारे फायदे मिलेंगे। जिसे नेचुरोपैथी एक्सपर्ट ने बताया है। साथ ही बताया कि किस तरह से और कब अमरूद खाना चाहिए जिससे इसके पूरे फायदे मिल सके। अमरूद में मौजूद विटामिन सी आर्टरीज को साफ रखने में मदद करता है। जिसकी ब्लॉकेज से हार्ट अटैक का खतरा होता है। यहीं नहीं अमरूद में मौजूद सॉल्यूएबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। जबकि पोटैशियम हाई बीपी को रेगुलेट करने में मदद करता है। वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स हार्ट सेल्स को होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में मदद करता है। अमरूद का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डायबिटीज रोगियों के लिए इसे बेस्ट फ्रूट बनाता है। वहीं इसमे बायो एक्टिव कंपाउंड इंसुलिन सेंसेटिविटी को बढ़ाते हैं।

सूखी खांसी से पाएं परमानेंट छुटकारा

एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और सर्दी लौटकर वापिस आ गई है। बारिश, कोहरा ने ठंड को बढ़ा दिया है और ऐसे में लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी बीमारियां घेर रही हैं। खांसी आना एक बार शुरू हो जाए, तो ये जल्दी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप भी लंबे समय से सूखी खांसी और जमे हुए बलगम की वजह से परेशान है और कफ सीरप से आराम नहीं मिला, तो आयुर्वेद डॉक्टर सलीम जैदी का असरदार नुस्खा एक बार ट्राई करके देख लें।

क्या है नुस्खा

डॉक्टर सलीम जैदी का कहना है कि आप अगर सूखी खांसी से तंग आ चुके हैं, तो एक बार गुड़ वाले नुस्खे को बनाकर खाएं। खांसी खत्म हो जाएगी और जमा हुआ बलगम भी निकल जाएगा। इसे बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी, चलिए बताते हैं ये नुस्खा क्या है और कैसे बनेगा।

क्या-क्या चाहिए

-1 चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, -1 चौथाई चम्मच काला नमक, -1 चम्मच अजवाइन, 4-5 दाने छोटी इलायची के, -1 चम्मच कसा हुआ अदरक, - गुड़-पानी।

कैसे बनाएं

अब आपको सभी चीजों को बताई गई मात्रा के हिसाब लेकर पीस लेना है और मिक्स करके रखना है। नॉन-स्टिक कढ़ाही लें और उसमें गुड़ और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पिघलाना शुरू करें। जैसे ही गुड़ पिघल जाता है, उसमें सभी मिक्स हुई चीजों को मिलाकर चलाएं। बस इसे 1-2 मिनट तक पकाना है और गैस से कढ़ाही उतार लें। हल्का ठंडा होने पर शीशी में भरकर रखें।

कैसे करें सेवन

इस नुस्खे को आधा चम्मच सुबह और रात को सोने से पहले खाएं और साथ में गुनगुना पानी पिएं। इस नुस्खे को आप सूखी या कफ वाली खांसी दोनों में खा सकते हैं। इसे खाने के बाद खट्टी और ठंडी चीजों से परहेज करें। ध्यान रखें कि 10 साल से छोटे बच्चों को ये न खिलाएं, नुकसान कर सकता है। बच्चे को हमेशा 1 चौथाई चम्मच ही ये खिलाना है। इसके अलावा स्मोकिंग भी करने से बचें। पुरानी खांसी है तो इस नुस्खे को 3 से 7 दिनों तक खाकर देखें, आराम मिलेगा।

सिरदर्द और दृष्टि हानि जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें

सिरदर्द और दृष्टि हानि जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें, ये ब्रेन ट्यूमर के संकेत हो सकते हैं। उल्हासनगर निवासी 55 वर्षीय अनिल बोराडे, जो आधारवाड़ी जेल में हेड कॉन्स्टेबल के रूप में कार्यरत हैं, तथा 36 वर्षीय अनिल सोनावणे, जो एक बीमा कंपनी में टीम लीडर हैं—दोनों को ठाणे स्थित सोलारिस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल से 'जीवनदान' मिला। दोनों मरीज पिट्यूटरी ग्रंथि के ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे, जिनके प्रमुख लक्षण सिरदर्द और दृष्टि हानि थे। इसके अलावा, स्ट्रोक से पीड़ित एक अन्य मरीज श्री जयदेव मुरपानी भी उपचार के लिए उल्हासनगर से आए थे और अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस संदर्भ में सोलारिस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर डॉ. दीपक ऐवले और डॉ. अमित ऐवले का कहना है, ''कृपया सिरदर्द, दृष्टि हानि और महिलाओं में हार्मोनल बदलाव जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें—ये ब्रेन ट्यूमर के संकेत हो सकते हैं। तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। ''ट्यूमर हटाने के लिए हॉस्पिटल ने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसे 'न्यूरो-नेविगेशन तकनीक' कहते हैं, जिसमें नाक के रास्ते ट्यूमर निकाला गया। यह एक मिनिमली इनवेसिव प्रक्रिया है, जिसमें मस्तिष्क को खोला नहीं जाता। इस सर्जरी के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ, ईएनटी सर्जन, महिला मरीजों के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट तथा न्यूरोसर्जन-सभी की संयुक्त (मल्टी-डिसिप्लिनरी) भागीदारी आवश्यक होती है। चूंकि दो भाइयों - न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. दीपक ऐवले और न्यूरोसर्जन डॉ. अमित ऐवलेद्वारा स्थापित सोलारिस अस्पताल में ये सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होने से सर्जरी सफलतापूर्वक करना आसान हुआ और मरीजों की दृष्टि बहाल करने के साथ कान संबंधी समस्याएं भी ठीक की गईं। पिछले ढाई वर्षों में सोलारिस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल ने इस नवीन न्यूरो-नेविगेशन तकनीक और मिनिमली इनवेसिव प्रक्रियाओं से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित 100 से अधिक मरीजों की जान बचाई है। सोलारिस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल उल्हासनगर में न्यूरोलॉजी और स्पाइन से संबंधित समस्याओं के लिए नि:शुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित कर रहा है। ब्रेन एवं स्पाइन ट्यूमर, पुराना सिरदर्द, दौरे (फिट्स), चक्कर (वर्टिगो), न्यूरोपैथी, मूवमेंट व बैलेंस डिसऑर्डर, मायस्थीनिया ग्रेविस आदि से पीड़ित लोग इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं। सोलारिस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के प्रमुख न्यूरोसर्जन एवं निदेशक डॉ. अमित ऐवले ने कहा, ''हमने ट्यूमर हटाने के लिए न्यूरो-नेविगेशन तकनीक का उपयोग किया। न्यूरो-नेविगेशन मस्तिष्क के लिए जीपीएस की तरह है, जो रियल-टाइम इमेजिंग के माध्यम से सर्जनों को अत्यंत सटीकता से ट्यूमर या समस्या वाले हिस्सों तक मार्गदर्शन देता है।

तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वितीय दिवस में हुआ व्यापक शैक्षणिक संवाद, प्रान्त संघचालक एवं पूर्व शिक्षा सचिव रहे अतिथि वक्ता, 104 शोध सारांश का हुआ प्रकाशन

समाधान महाविद्यालय में एनईपी-2020, सतत शिक्षा एवं मानवीय चेतना पर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श

बेमेतरा। सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति द्वारा संचालित समाधान महाविद्यालय, बेमेतरा में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वितीय दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सतत शिक्षा एवं मानवीय चेतना विषय पर एक विशेष पैरेलल सत्र का आयोजन किया गया। सत्र का विषय सस्टेनबल एजुकेशन फॉर ह्यूमन एन्ड प्लेनटेरी वेलबीइंग रहा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए शिक्षाविदों, नीति विशेषज्ञों एवं विषय-विशेषज्ञों ने सहभागिता की। सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रांत संघचालक डॉ. टोपलाल वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित स्व-आधारित जीवन शैली को शिक्षा के केंद्र में लाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा को केवल कौशल या रोजगार तक सीमित न रखकर चेतना, संस्कार और आत्मनिर्भर सोच से जोड़ा जाना चाहिए। कीनोट सत्र में वक्ताओं ने एनईपी-2020 के विभिन्न आयामों पर विचार रखे। डॉ. शारदा शर्मा (अम्बा दीदी), अमरकंटक ने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था मुख्यतः धनोपार्जन पर केंद्रित हो गई है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य मानव को सही कार्य-व्यवहार और संबंधों की समझ देना होना चाहिए। पूर्व कुलपति डॉ. अरुणा पल्टा ने बताया कि एनईपी-2020 का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों का बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं चरित्रगत विकास करना है तथा सतत शिक्षा एवं मूल्यांकन मानव और विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है। रजिस्ट्रार डॉ. भूपेंद्र कुलदीप ने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए शिक्षा, ज्ञान और चेतना का एकीकरण अनिवार्य है। डॉ. संकेत ठाकुर ने स्पष्ट किया कि सतत विकास तभी संभव है जब मानवीय चेतना का विकास हो, अन्यथा विकास अस्थायी रह जाता है। डॉ. अशोक ठाकुर, डायरेक्टर, मुनि इंटरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को विधिपूर्वक लागू करने से विद्यार्थियों में चेतना जागृत होती है तथा सहयोग की भावना विकसित होती है, जिससे छात्र स्वयं समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनते हैं। नंदकुमार डी. जी., आईएएस, पूर्व शिक्षा सचिव ने कहा कि भविष्य की शिक्षा का आधार स्व-अध्ययन, पीयर लर्निंग, जिज्ञासा, तकनीकी उपयोग और सीखने की गति के अनुसार वातावरण निर्माण होना चाहिए। इसके लिए सशक्त नेतृत्व और सही प्रबंधन आवश्यक है। डॉ. राकेश मुदृल, कुलपति आत्मीय विश्वविद्यालय, गुजरात ने कहा कि ज्ञान से क्षमता, मूल्यों से दिशा और नैतिकता से कार्यवाही निर्धारित होती है। डॉ. सुरेंद्र पाठक ने विज्ञान, अध्यात्म और मानवीय चेतना के एकीकरण को सतत विकास की आधारशिला बताया। अन्य वक्ताओं में सुशील कुमार राठौर ने एनईपी-2020 के संदर्भ में मानसिकता परिवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अनीता शाह एवं चानी चावड़ा ने चेतना विकास आधारित मूल्य शिक्षा को एनईपी-2020 के लक्ष्यों की पूर्ति का प्रभावी माध्यम बताया। अंकित पोगुला ने जीवन के लक्ष्य की स्पष्टता को शिक्षा का मूल उद्देश्य बताया। डॉ. अंजली औधिया ने विज्ञान और नैतिकता के समन्वय को आवश्यक बताते हुए कहा कि दोनों मिलकर ही मानव मूल्यों को दिशा दे सकते हैं। सम्मेलन में 104 शोध सारांशों का प्रकाशन, प्रोसीडिंग बुक का विमोचन तथा शैक्षणिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

पैनल एक्सपर्ट के रूप में प्रो. विद्यानंद पाण्डेय एवं डॉ. बृजेश प्रताप यादव उपस्थित रहे। प्रतिभागियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कायक्रम का संचालन महाविद्यालय के डायरेक्टर एवं सचिव डॉ अवधेश पटेल एवं सहायक प्राध्यापक हरीश कुमार पटेल ने किया तथा अंत में महाविद्यालय के डायरेक्टर अविनाश तिवारी ने आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष सीता वर्मा में स्वागत किया। सम्मेलन में बेमेतरा जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए 150 से अधिक शिक्षकों, सहायक प्राध्यापकों, रिसर्च स्कॉलर की सहभागिता रही।

चीचा ग्राम पंचायत की दुर्गा पटेल बनीं 'लखपति दीदी', स्व-सहायता समूह से मिली आर्थिक आत्मनिर्भरता

दुर्ग। दुर्ग जिले की चीचा ग्राम पंचायत अंतर्गत चीचा गाँव की निवासी दुर्गा पटेल ने बहुआयामी आजीविका गतिविधियों को अपनाकर उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हासिल की है। वर्तमान में वे लखपति दीदी के रूप में पहचानी जाती हैं। दुर्गा पटेल माँ शाकाम्बरी स्व-सहायता समूह की सक्रिय सदस्य हैं। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें विभिन्न कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने घर पर ब्यूटी पार्लर का कार्य शुरू किया, जिससे उन्हें प्रतिमाह लगभग तीन से पांच हजार रुपये की आय होने लगी। साथ ही उनका चयन पशु सखी के रूप में हुआ। इस भूमिका में वे पशुओं का टीकाकरण, पोषण संबंधी परामर्श और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराती हैं। इस सेवा से उन्हें प्रतिमाह लगभग 1910 रुपये की आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अपने घर की बाड़ी में सब्जियों की खेती शुरू की, जिससे उन्हें प्रतिमाह छह से आठ हजार रुपये की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो रही है। इन सभी गतिविधियों के माध्यम से दुर्गा पटेल ने नियमित और सतत आय अर्जित कर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। उनकी यह सफलता शासन की आजीविका संवर्धन योजनाओं और स्व-सहायता समूहों की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। वर्तमान में वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक मजबूती के लिए प्रेरणा बन रही हैं, बल्कि गाँव की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रोत्साहित कर रही हैं। राज्य सरकार का धन्यवाद करते हुए पटेल ने कहा कि आजीविका संवर्धन योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण और स्व सहायता समूह के सहयोग से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर प्रदान किया।

महापौर अलका बाघमार ने प्रभारी काशीराम कोसरे व अधिकारियों संग किया तैयारियों का निरीक्षण

राजेंद्र पार्क में 14 फरवरी को भव्य फ्लावर शो का आयोजन

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा आगामी 14 फरवरी को राजेंद्र पार्क में भव्य फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राजेंद्र पार्क रंग-बिरंगे फूलों से सुसज्जित रहेगा, जहां बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी एवं नागरिकों के पहुंचने की संभावना है। फ्लावर शो की तैयारियों को लेकर आज महापौर अलका बाघमार ने पर्यावरण प्रभारी काशीराम कोसरे, एमआईसी सदस्य देवनारायण चंद्राकर, शेखर चंद्राकर, नीलेश अग्रवाल, खालिक रिजवी एवं उद्यान प्रभारी अनिल सिंह के साथ राजेंद्र पार्क का निरीक्षण किया। नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर फ्लावर शो कार्यक्रम हेतु कार्यपालन अभियंता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। महापौर अलका बाघमार के निर्देश पर पर्यावरण विभाग प्रभारी काशीराम कोसरे द्वारा जानकारी दी गई कि फ्लावर शो में पारिवारिक वातावरण के अनुरूप मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें भाग लेने हेतु प्रतिभागियों के लिए अलग-अलग स्टॉल भी बनाए जाएंगे। फ्लावर शो में भाग लेने के लिए दिनांक 3 फरवरी से पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। इच्छुक प्रतिभागी प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक राजेंद्र पार्क पहुंचकर पंजीयन करा सकते हैं। निरीक्षण के दौरान महापौर एवं पर्यावरण प्रभारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजेंद्र पार्क में रंग-रोहन, झूलों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। साथ ही दादा-दादी नाना-नानी पार्क से राजेंद्र पार्क तक आवागमन सुविधा के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। फ्लावर शो के अंतर्गत निःशुल्क 40 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही वन विभाग एवं संजीवनी संस्था को आमंत्रित करने हेतु पत्राचार किया जाएगा, जिससे कार्यक्रम और अधिक आकर्षक एवं उपयोगी बन सके।

संभागायुक्त राठौर ने न्यायालयीन आदेश पारित कर अपराधी को केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने दिये आदेश

दुर्ग। दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने पुलिस अधीक्षक खैरागढ़-गंडई-छुईखदान के प्रतिवेदन पर स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार, निवारण अधिनियम-1988 की धारा-3 सहपठित धारा-11 के तहत न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मेहरून निशा पति ईस्माईल खान निवासी वार्ड-08, माहरापारा थाना गंडई जिला खैरागढ़-गंडई-छुईखदान को 03 माह के लिए केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने आदेशित किया है। आदेश पारित करने के पूर्व संभाग आयुक्त द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब/तर्क, न्याय दृष्टांतों एवं शपथपूर्वक कथन का अध्ययन कर उस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत ईश्तगासा मय दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है। तथ्य के अनुसार मेहरून निशा पति ईस्माईल खान के विरूद्ध नारकोटिक्स एक्ट के 02 मामले दर्ज कर कार्यवाही की गई है। जिसमें अपराध क्रमांक 105/2023 एवं 190/2025 वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अनावेदिका जमानत पर जेल से छूट जाने के पश्चात् लगातार मादक पदार्थ में खरीदी-बिक्री में संलिप्त रही है तथा उसकी प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं हुई है। वर्तमान में भी अनावेदिका के विरूद्ध गांजा सहित अन्य मादक पदार्थ बेचने की शिकायते लगातार मिलती रही है। स्वतंत्र साके शपथपूर्वक बयान में भी अनावेदिका द्वारा जेल से छूटने के बाद पुनः मादक पदार्थ विक्रय करने में संलिप्त रहने का तथ्य प्रकाश में आया है। जमानत पर न्यायालय से छूट जाने से उसका मनोबल बढ़ता जा रहा है। उनकी आपराधिक गतिविधियों से समाज में रहने से विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया।

ग्राम पंचायत सांकरा में बनेगा 1200 मीटर सीसी रोड, हुआ भूमिपूजन

अम्लेश्वर। जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सांकरा में सीसी रोड का भूमि पूजन जनपद सदस्य प्रणव शर्मा के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। आपको बता दें ग्राम सांकरा में लोक निर्माण विभाग के द्वारा 2 करोड़ 39 लाख के लागत से 1200 मीटर सीसी रोड का निर्माण किया जाना है। जिसका विधिवत भूमि पूजन जनपद सभापति प्रणव शर्मा, ग्राम पंचायत के युवा सरपंच रवि सिंगौर के द्वारा नारियल तोड़कर किया गया। ग्राम पंचायत के युवा सरपंच रवि सिंगौर ने मीडिया को जानकारी शेयर करते हुए कहा कि विष्णु के सुशासन में लोगों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। लगातार मोदी के गारंटी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य किया जा रहा है। जिसका प्रमाण आज ग्राम सांकरा में देखने को मिल रहा है। निश्चित ही भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ काम करने वाली पार्टी है। इस अवसर पर उपसरपंच रामशरण बंधे, तुलाराम सिंगौर पंच, महेंद्र पारधी पंच ,वीरेंद्र यादव पंच ,विकास सिंगौर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

वार्ड 38 ऋषभ नगर को मिली बड़ी सौगात, 12 लाख के डामरीकरण कार्य का भूमिपूजन

महापौर अलका बाघमार ने किया ऋषभ नगर में डामरीकरण कार्य का शुभारंभ

दुर्ग। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 38 ऋषभ नगर में महापौर अलका बाघमार द्वारा 12 लाख रुपये की लागत से डामरीकरण निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया गया। यह डामरीकरण कार्य ऋषभ नगर जैन मंदिर से लेकर ऋषभ नगर गार्डन तक किया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को लंबे समय से चली आ रही सड़क समस्या से राहत मिलेगी।

भूमिपूजन कार्यक्रम में लोक कर्म प्रभारी देवनारायण चंद्राकर, एमआईसी सदस्य शेखर चंद्राकर, ज्ञानेश्वर ताम्रकर, नीलेश अग्रवाल, पार्षद रामचंद्र सेन एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कांतिलाल बोथरा,मंडल अध्यक्ष महेंद्र लोढ़ा भूमिपूजन कार्यक्रम उपस्थित रहे। साथ ही निगम उपअभियंता मोहित मरकाम, आर.के. जैन सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। ऋषभ नगर क्षेत्र के रहवासियों ने लंबे समय से लंबित डामरीकरण कार्य की मांग पूरी होने पर महापौर अलका बाघमार के प्रति आभार व्यक्त किया और निगम प्रशासन की सक्रियता की सराहना की। इस अवसर पर नागरिकों ने क्षेत्र में अन्य आवश्यक विकास कार्यों को लेकर भी महापौर से चर्चा की। महापौर ने आश्वस्त किया कि नगर के समग्र विकास के लिए निगम प्रतिबद्ध है तथा सभी वार्डों में चरणबद्ध रूप से आवश्यक निर्माण एवं विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डामरीकरण कार्य गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण कराया जाएगा, ताकि नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सके।

एसआईआर सत्यापन के चक्रव्यूह से वयोवृद्ध प्रोफेसर परेशान

कुम्हारी। वार्ड क्रमांक 15, कुम्हारी (पाटन) के 88 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर यज्ञ व्रत श्रीवास्तव, जो विगत चार वर्षों से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके भौतिक सत्यापन हेतु जारी एस.आई.आर. नोटिस ने प्रशासनिक नियमों की व्यवहारिकता पर प्रश्नचिह्न लगा है। स्थानीय पार्षद अनुराग गुप्ता ने अपनी ओर से समाधान के लिए प्रयास भी किया था, फिर भी 7 फरवरी 2026 को बीएलओ का घर पर पहुंचकर औपचारिकताओं के लिए विवश करना, एक बड़ी नीतिगत खामी की ओर ध्यान खींचती है। मेडिकल प्रोटोकॉलः 'सघन मानवीय निगरानी' ही एकमात्र सुरक्षा कवच मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रोफेसर श्रीवास्तव हार्ट फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज (सी.के.डी.) और हृदय रोग जैसी मल्टी-ऑर्गन बीमारियों से पीड़ित हैं।। निरंतर दवाओं के सेवन के कारण शरीर में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस बिगड़ने का खतरा हर पल बना रहता है, जिसकी वजह से सतत मानवीय निगरानी अनिवार्य है। साथ ही गंभीर उम्र सम्बन्धी बीमारियों के कारण डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से 'मॉनिटरिंग वाइटल्स' का निर्देश दिया है। विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार, ऐसी जटिल बीमारी की स्थितियों में मृत्यु का जोखिम चिकित्सकीय रूप से अत्यंत अधिक माना जाता है; इसलिए देखरेख की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की मानवीय चूक, अनुभवी प्राथमिक केयर टेकर की अनुपस्थिति या मॉनिटरिंग में लम्बा अंतराल मरीज के जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, , क्योंकि आपात स्थिति में समय रहते उपचार की व्यवस्था ही रोगी की सुरक्षा का प्रमुख आधार होती है।

साँसों पर पहराः रात भर 'वाइटल्स' की निगरानी-बेटे शील रत्न श्रीवास्तव ने बताया कि विगत चार वर्षों से बीमार पिता की निरंतर सुरक्षा अखंड चिकित्सकीय अनुशासन, 'कठोर मेडिकल प्रोटोकॉल' और 'सतत सघन मानवीय देखभाल ' पर टिकी है। शुगर लेवल का अचानक गिरना (हाइपोग्ला इसीमिया), इलेक्ट्रोलाइट्स में बदलाव, यूरिन आउटपुट, पल्स रेट, रक्तचाप और ऑक्सीजन के स्तर में असाधारण बदलाव आने का जोखिम हर पल बना रहता है, जिसके कारण अक्सर पूरी रात जागकर देखरेख करनी पड़ती है। घर को ही एक 'सघन मानवीय देखभाल कक्ष' के रूप में तब्दील कर सारे वाइटल्स पैरामीटर्स पर नजर रखना ही इस सुरक्षा कवच का आधार है। चिकित्सकीय विवशता के कारण, बेटे ने पूर्व में मरीज को गैर-अनुभवी अटेंडेंट के भरोसे अकेला छोड़कर दफ्तर पहुँचने में अपनी व्यावहारिक असमर्थता व्यक्त की थी।

निजी भूमि पर टावर स्थापना का मुआवजा लंबित, किसान ने जनदर्शन में लगाई गुहार

पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिलने से किसान परेशान, दिया आवेदन

दुर्ग। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में डिप्टी कलेक्टर हितेश पिस्दा भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 130 आवेदन प्राप्त हुए। इसी कड़ी में ग्राम मंचादुर के किसान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि दिलाने की मांग की। कृषक ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि पिछले एक वर्ष से नहीं मिल रही है। किसान योजना का पात्र लाभार्थी है और पहले नियमित रूप से राशि मिलती रही है। किसान का कहना है कि आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर सभी सही व अद्यतन हैं, फिर भी किस्त अटकी हुई है। इस पर कलेक्टर ने कृषि विभाग को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। इसी प्रकार ग्राम मचान्दर के एक अन्य कृषक ने मुआवजा राशि प्राप्त नही होने की शिकायत की। किसान ने बताया कि उनकी भूमि पर पावरग्रिड द्वारा टावर स्थापित किया गया है, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा राशि नहीं दी गई। मुआवजा गणना पत्रक में पास की भूमि के एक अन्य व्यक्ति का नाम शामिल हो गया है, जबकि वास्तविक प्रभावित भूमि स्वामी को भुगतान नहीं किया गया। पीड़ित किसान ने अनुविभागीय भू-अर्जन अधिकारी से मामले की जांच कर सही हितग्राही को मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग को मामले की जांच कर सही हितग्राही को मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए। पोटियाकला के पार्षद ने स्पीड ब्रेकर लगवाने आवेदन दिया। वार्ड क्रमांक 54 पोटियाकला में स्थित पोटिया स्कूल के सामने सड़क पर लगातार तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। स्कूल क्षेत्र में तीन से चार स्थानों पर स्पीड ब्रेकर जल्द बनवाने आवेदन दिया, ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लग सके और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस पर कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग को निरीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही करने को कहा। इस दौरान जनदर्शन में विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

नो मेपिंग तथा तार्किक विसंगतियां संबंधी दस्तावेज सत्यापन की जानकारी देने के निर्देश

हुड़को से अवैध अतिक्रमण हटाने की गई कार्यवाही

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत शहर को कब्जा मुक्त बनाने लगातार अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन आयुक्तों को निर्देशित किये है कि कहीं भी सड़क किनारे, नालियों एवं अन्य स्थल पर अवैध अतिक्रमण पाया जाता है, तो तत्काल अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावें।जोन-5 अंतर्गत मुख्य सड़क मार्ग पर अनाधिकृत स्थान पर किये गये अतिक्रमण को जे.सी.बी. से हटाने की कार्यवाही की गई। साथ ही सड़क किनारे अवैध रूप से पैथालाजी लैब का बोर्ड लगाया गया था, बढ़ते सड़क दुर्घटना को देखते हुए बोर्ड को हटाया गया। कार्यवाही के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, दुर्योधन साहू, गणित बघेल, टेकराम हरिन्द्रवार, विनोद यादव, गेंद प्रसाद सहित राजस्व विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। Email : loktantraprahrinews@gmail.com